RNI No. DLHIN/25/A2321

DD

दिव्य दिल्ली

दिल्ली से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र

वर्ष: 01, अंक: 26, पृष्ठ: 08

infodivyadelhi@gmail.com

सोमवार, 06 अक्टूबर, 2025 तदनुसार 19 भाद्रपद विक्रमी सम्वत 2082 | www.divyadelhi.com | facebook.com/divyadelhi

तापमान अधिकतम 30 डिग्री न्यूनतम 25 डिग्री

सूर्योदय 05.25 | सूर्यास्त 06.50

चुनाव बाद एसआईआर का मतलब नहीं था: चुनाव आयोग

राजेश चौहान
पटना

भोजपुरी में बिहार के मतदाताओं का अभिवादन करते हुए देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को पटना में कहा कि जिस तरह हम अपने पर्व-त्योहारों और विशेष रूप से लोक आस्था के महापर्व छठ को मनाते हैं, उसी तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान को उत्साह के साथ मनाएं। उन्होंने मतदान की तारीखों पर फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन यह जरूर कहा कि 22 नवंबर से पहले चुनाव की पूरी प्रक्रिया संपन्न करा ली जाएगी।

जो प्रत्याशी खड़े हों, वह पोलिंग एजेंट्स जरूर दें। मॉक पोल अपनी आंखों के सामने जरूर देखने कहें। मतदान के खत्म होते समय पोलिंग एजेंट्स फॉर्म 17सी भी ले लें। जिन लोगों को नगर निगम ने मकान का कोई नंबर तय नहीं किया है, वहां एक ही मकान में कई लोगों के नंबर मतदाता सूची में दर्ज होने की आशंका रहती है। क्योंकि, कुछ चिह्नित करने के लिए बीएलओ यह करते हैं। चुनाव के पहले पुनरीक्षण हर बार होता है, इसलिए उसे चुनाव के बाद कराने की मांग का कोई अर्थ नहीं है। बिहार के एसआईआर में दावा-आपत्ति का पूरा अवसर दिया गया। इस प्रक्रिया की देखरेख के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपने बूथ लेवल एजेंट्स दिए थे। एसआईआर में अब भी समय है कि किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल को ऐसा लगता है कि योग्य मतदाता छूट गया है या अयोग्य मतदाता का नाम सूची में है तो वह दावा-आपत्ति कर सकता है।

उनके दावे-आपत्ति का निपटारा ईआरओ स्तर से हो जाएगा। जिनके वोटर कार्ड के डाटा में कोई परिवर्तन होगा, उन्हें 15 दिनों के अंदर ईपिक मिल जाएगा। वोटर की जांच किस तरह करनी है, उसी के तहत जांच की गई है।

पहली बार दिल्ली में ट्रेनिंग, मानदेय बढ़ाया जाना उपलब्धि

बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विभिन्न स्तरों पर बैठक कर चुके हैं। मुख्य सचिव, बाकी विभागीय सचिवों और डीजीपी के साथ भी बैठक कर चुके हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने जानकारी दी कि बूथ लेवल एजेंट्स की पहली बार चुनाव आयोग ने ट्रेनिंग की। बिहार के सभी बूथ लेवल एजेंट्स- 1 की ट्रेनिंग कुछ माह पहले ही दिल्ली में ट्रेनिंग हुई। उसके बाद बूथ लेवल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग हुई। इसके बाद देशभर के 700 बूथ लेवल सुपरवाइजर्स-एजेंट्स की ट्रेनिंग की गई। मतदाता सूची के मामले में विशेष गहन पुनरीक्षण बड़ा टास्क था। सभी मतदाताओं के सहयोग के साथ स-समय यह पूरा हुआ।

मतदाता बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी: ज्ञानेश

जिन लोगों ने मतदाता सूची के लिए नामांकन भरा होगा, वह आधार देने के लिए बाध्य नहीं हैं। चुनाव आयोग, आधार अथॉरिटी के नियम और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत आधार न जन्मतिथि और न ही नागरिकता का प्रमाणपत्र है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो हमने पुनरीक्षण में आधार कार्ड लेने की व्यवस्था दी। संविधान के तहत, मतदाता बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। वोटर जहां रहता है, उसके आसपास के बूथ का मतदाता हो सकता है। गैर-भारतीय होने के आधार पर कितने नाम कटे, इसपर मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्पष्ट जानकारी नहीं दी। उन्होंने कहा कि सभी चिह्नित अयोग्य मतदाताओं का नाम हटाया गया है। इसकी सूची जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के पास भी है और राजनीतिक दलों के पास भी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि एससी 2 और एसटी 38 समेत बिहार में 243 सीटें हैं। दो दिनों के इस भ्रमण के पहले भी चुनाव आयोग के अधिकारियों ने पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों के साथ ही बैठक हो चुकी है।

ट्रंप ने भारत पर टैरिफ शायद अहंकार में लगाया है: विशेषज्ञ

नई दिल्ली

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और चीनी मामलों के विशेषज्ञ श्रीकांत कोंडापल्ली ने शनिवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संभवतः अपने अहंकार के चलते भारतीय आयात पर टैरिफ लगाया है, जबकि मुख्य मुद्दा हमेशा से चीन द्वारा अमेरिका के वैश्विक आधिपत्य को चुनौती देना रहा है। यदि ट्रंप का गुस्सा ट्रेड सरप्लस को लेकर है, तो यह वास्तव में चीन पर होना चाहिए, न कि भारत पर। भारत इस मुद्दे पर परिदृश्य में ही नहीं है। यह मामला शायद व्यक्तिगत अहंकार के कारण सामने आया, जैसे नोबेल पुरस्कार या संघर्ष विराम।

दार्जिलिंग में बारिश से तबाही: भूस्खलन और पुल टूटने की घटना में 17 लोगों की

कोलकाता

उत्तर बंगाल में लगातार भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त है। दार्जिलिंग जिले में हुए भूस्खलन और पुल टूटने की घटनाओं में अब तक 17 लोगों की मौत हो गई है और दो लोग लापता बताए जा रहे हैं। मौक का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। जानकारी के मुताबिक, मिरिक और सुखिया क्षेत्रों में भूस्खलन के कारण कई लोग हताहत हुए हैं। इस हादसे के बाद दार्जिलिंग जिला पुलिस राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। वहीं कालिम्पोंग में स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। लगातार बारिश से कई इलाकों का संपर्क टूट गया है और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

पीएम मोदी ने जनहानि पर जताया दुख

प्रधानमंत्री मोदी ने दार्जिलिंग में पुल ढहने की घटना पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा- दार्जिलिंग में एक पुल दुर्घटना में हुई जान-माल की हानि से अत्यंत दुःखी हूं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। भारी बारिश और भूस्खलन के मद्देनजर दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों की स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। हम प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस हादसे पर दुख जताया है। एक्स पर राष्ट्रपति भवन की तरफ से किए पोस्ट में लिखा गया- पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण हुई दुखद जनहानि अत्यंत दुखद है।

'रूस ने पाकिस्तान को नहीं बेचे जेएफ-17 के इंजन', भाजपा ने कहा- कांग्रेस फैला रही भारत विरोधी जानकारी

नई दिल्ली

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता अमित मालवीय ने रविवार को रूस की तरफ से पाकिस्तान को RD-93MA इंजन सप्लाई करने की खबरों को पूरी तरह से खारिज किया। उन्होंने कहा कि ऐसी किसी भी सप्लाई की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और ना ही कोई विश्वसनीय स्रोत है। अमित मालवीय ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा- कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक रिपोर्ट पर भरोसा किया, जिसमें एक ऐसे वेबसाइट का हवाला दिया गया जो 'प्रो-पाकिस्तान प्रोपेगेंडा' फैलाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि जयराम रमेश इस खबर के जरिए जानबूझकर भारत विरोधी जानकारी फैला रहे हैं।

'कांग्रेस नेता ने फिर से दुश्मन के साथ खड़े होने का रास्ता चुना'

अमित मालवीय ने लिखा, 'कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं, कोई विश्वसनीय स्रोत नहीं। यह सिर्फ एक और बेतुकी जानकारी की लड़ाई है। कांग्रेस के संचार प्रमुख ने फिर से दुश्मन के साथ खड़े होने का रास्ता चुना है, बजाय इसके कि वे भारत के साथ खड़े हों।'

जयराम रमेश ने क्या लगाए थे आरोप?

इससे एक दिन पहले, जयराम रमेश ने कहा था कि रूस, जो कभी भारत का करीबी सहयोगी माना जाता था, पाकिस्तान को जेएफ-17 थंडर ब्लॉक III लड़ाकू विमानों के लिए RD-93MA इंजन सप्लाई कर रहा है। रमेश ने आरोप लगाया कि भारत की अपीलों के बावजूद यह सौदा आगे बढ़ रहा है।

जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा था कि मोदी सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि रूस, जो भारत का लंबे समय तक भरोसेमंद सहयोगी रहा है।

मीरा रोड में गरबा कार्यक्रम में फेंका गया अंडा

ठाणे

महाराष्ट्र के मंत्री और भाजपा विधायक नितेश राणे ने राज्य के मीरा रोड इलाके में एक हाउसिंग सोसाइटी में हुए गरबा कार्यक्रम पर अंडा फेंकने की घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने साफ कहा कि 'जिहादी मानसिकता' वाले लोग बख्शे नहीं जाएंगे। यह घटना रात 10.30 बजे से 11 बजे के बीच हुई, जब एक व्यक्ति ने कथित तौर पर 16वीं मंजिल से जेपी नॉर्थ गार्डन सिटी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के कॉमन एरिया में अंडा फेंक दिया। पुलिस ने इस व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 300 के तहत मामला दर्ज किया है। यह धारा धार्मिक पूजा या समारोह में बाधा डालने वालों पर लागू होती है।

पत्नी की कॉल रिकॉर्डिंग को सबूत के तौर पर किया जा सकता है इस्तेमाल: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने एक पति की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें उसने अपनी पत्नी की फोन पर हुई बातचीत को लंबित तलाक के मामले में सबूत के तौर पर इस्तेमाल करनी की मांग की थी।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पति के कृत्य किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं। बता दें कि पति ने किसी बिना पूर्व सूचना के ही अपनी पत्नी की फोन पर हुई बातचीत को रिकॉर्ड किया था।

रिपोर्ट के अनुसार, देश के शीर्ष न्यायालय ने पंजाब एवं हरियाणा के उच्च न्यायालय के उस फैसले को भी पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि पति को अपनी पत्नी की अनुमति के बिना जानकारी रिकॉर्ड

की गई बातचीत को सबूत के तौर पर नहीं पेश किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने कहा था कि तलाक की कार्यवाही में उसकी निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा।

जानिए क्या है पूरा मामला?

पूरा मामले एक दंपती के तलाक से जुड़ा हुआ है। दंपती का विवाह 20 फरवरी 2009 को हुआ था और 11 मई 2011 को उनकी एक बेटी हुई थी। हालांकि, चल रहे वैवाहिक विवादों के कारण पति ने 7 जुलाई 2017 को पारिवारिक न्यायालय में तलाक के लिए अर्जी दी। इसके बाद 3 अप्रैल 2018 को उसने तलाक की याचिका में संशोधन किया और 7 दिसंबर 2018 को जांच के लिए अपना हलफनामा प्रस्तुत किया।

पति ने मांगी रिकॉर्ड की गई बातों को प्रस्तुत करने की अनुमति

बाद में 9 जुलाई 2019 को पति ने मोबाइल फोन के मेमोरी कार्ड/चिप, एक कॉम्पैक्ट डिस्क और रिकॉर्ड की गई बातचीत के ट्रांसक्रिप्ट जैसे साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी।

बारिश से प्रभावित किसानों को हर संभव मदद देगी सरकार: शाह

हाल ही में हुई भारी बारिश से 60 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि प्रभावित हुई है: शाह

मुंबई

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार महाराष्ट्र में भारी बारिश से नुकसान झेलने वाले किसानों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। शाह ने यह बात डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटिल कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री की विस्तारित क्षमता के उद्घाटन के बाद किसानों की रैली को संबोधित करते हुए कही। इससे पहले महाराष्ट्र के एक दिवसीय दौरे पर आए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शिरडी स्थित साईंबाबा मंदिर में रविवार को पूजा-अर्चना की। अमित शाह के साथ राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एवं अजित पवार तथा अन्य लोग भी मौजूद रहे। किसान रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि हाल ही में हुई भारी बारिश से 60 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि प्रभावित हुई है। महाराष्ट्र के कई

हिस्सों में हाल में हुई भारी बारिश और बाढ़ आने से व्यापक नुकसान हुआ है ।शाह ने कहा, मैंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों उपमुख्यमंत्रियों एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ एक विस्तृत बैठक की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से, मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि एक बार विस्तृत रिपोर्ट हमें सौंप दिए जाने के बाद, प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के किसानों को कोई भी मदद देने में देरी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पिछले वर्ष की सहायता में से 3,132 करोड़ रुपये पहले ही जारी कर चुकी है, जिसमें इस वर्ष अप्रैल में दी गई 1,631 करोड़ रुपये की सहायता भी शामिल है। शाह ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने भी 2,215 करोड़ रुपये की राहत राशि प्रदान की है, जिससे 31 लाख से ज्यादा किसानों को लाभ हुआ है। गृह मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों की परेशानी कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

भारत के लिए अब भी रूस नंबर वन विकल्प', कच्चा तेल को लेकर एक्सपर्ट ने किया खुलासा

नई दिल्ली

अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाने के बावजूद भी भारत रूस से कच्चा तेल खरीदने के मामले में पीछे नहीं है। सितंबर में रूस से भारत के कच्चे तेल के आयात में मामूली गिरावट देखने को मिला। लेकिन देश की कुल तेल खरीद का एक तिहाई से अधिक हिस्सा रूस से खरीदा। इसको लेकर चिंतित अमेरिका ने व्यापार पर अंकुश लगाने का दबाव बनाते हुए आरोप लगाया कि रूस यूक्रेन में मास्को के युद्ध प्रयासों का समर्थन करता है। सितंबर में भारत का कच्चा तेल आयात लगभग 4.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन था, जो महीने-दर-महीने 2,20,000 बैरल प्रतिदिन अधिक और साल-दर-साल स्थिर रहा। रूस कच्चा तेल आपूर्ति के मामले में नबंर वन स्थिति बनाए रखा। इसका योगदान लगभग 1.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन था - जो 34 प्रतिशत हिस्सेदारी है। हालांकि, वैश्विक व्यापार विश्लेषण फर्म केप्लर के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, 2025 के पहले आठ महीनों के दौरान आयातित औसत रूसी मात्रा से लगभग 1,60,000 बैरल प्रतिदिन कम था।

भारत के लिए सबसे अच्छा विकल्प रूस

केप्लर के प्रमुख रिसर्च विशेषज्ञ (रिफाइनिंग एवं मॉडलिंग) सुमित रिटोलिया ने कहा कि कच्चे तेल के आयात में गिरावट के बावजूद, रूसी बैरल भारतीय रिफाइनरों के लिए सबसे किफायती फीडस्टॉक विकल्पों में नबंर वन है। क्योंकि इनके उच्च GPW (सकल उत्पाद मूल्य) मार्जिन और विकल्पों की तुलना में छूट मिलती है। इराक भारत का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता था, जहां से लगभग 8,81,115 बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल आयात होता था। इसके बाद दूसरे नंबर पर सऊदी अरब था। जहां से 6,03,471 बैरल प्रतिदिन आयात होता रहा।, संयुक्त अरब अमीरात भी 5,94,152 बैरल प्रतिदिन के साथ दूसरे स्थान पर था। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका 2,06,667 बैरल प्रतिदिन के साथ भारत का पांचवां सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रह चुका है।

लद्दाख हिंसा: जेल से सोनम वांगचुक ने की शांति की अपील

नई दिल्ली

लद्दाख हिंसा के बाद जेल में बंद सोनम वांगचुक ने लेह विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई चार लोगों की मौत की स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब तक यह मांग पूरी नहीं हो जाती, वह जेल में रहने को तैयार हैं। वांगचुक वर्तमान में जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। पुलिस ने उन्हें 26 सितंबर को हिरासत में लिया था। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के नेता सज्जाद कारगिली ने एक्स पर पोस्ट सोनम वांगचुक का संदेश शेयर किया है। सोनम से उनके भाई कात्सेतन दोरजे ले और वकील मुस्तफा हाजी ने 4 अक्टूबर को जेल में उनसे मुलाकात की थी। सज्जाद कारगिली ने एक्स पर लिखा, जोधपुर सेंट्रल जेल से सोनम वांगचुक का संदेश..... 4 अक्टूबर को कात्सेतन दोरजे ले (सोनम वांगचुक के बड़े भाई) और अधिवक्ता मुस्तफा हाजी ने जोधपुर सेंट्रल जेल में सोनम वांगचुक से मुलाकात की। उन्होंने अपने वकील के माध्यम से कहा, मैं शारीरिक और

मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ हूं और सभी की चिंता और प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद देता हूं। उन लोगों के परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना, जिन्होंने अपनी जान गंवाई और जो लोग घायल हुए हैं और गिरफ्तार हुए हैं। हमारे चार लोगों की हत्या की एक स्वतंत्र न्यायिक जांच होनी चाहिए और जब तक ऐसा नहीं होता, मैं जेल में रहने के लिए तैयार हूं। सोनम ने अपने संदेश में कहा कि मैं 6ठी अनुसूची और राज्य का दर्जा पाने की हमारी वास्तविक संवैधानिक मांग में सर्वोच्च निकाय, केडीए और लद्दाख के लोगों के साथ दृढ़ता से खड़ा हूं। सर्वोच्च निकाय लद्दाख के हित में जो भी कदम उठाएगा, मैं तहे दिल से उनके साथ हूं। मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे शांति और एकता बनाए रखें, और अहिंसा के सच्चे गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से अपना संघर्ष जारी रखें।

कल सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी पर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट सोमवार को पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। इस याचिका में वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत की गई गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है और उनकी तत्काल रिहाई की मांग की गई है।

अब नई भूमिका में दिखेंगे शुभांशु शुक्ला, छात्रों को बनाएंगे विकसित भारत के निर्माता

नई दिल्ली

अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) तक पहुंचने वाले भारतीय ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को केंद्र सरकार के 'विकसित भारत बिल्डाथॉन' का ब्रांड एंबेसडर बनाया गया है। यह कार्यक्रम देशभर के स्कूलों में नवाचार और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है।

देश का सबसे बड़ा स्कूल हैकाथॉन

'विकसित भारत बिल्डाथॉन' शिक्षा मंत्रालय और अटल इनोवेशन मिशन के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। यह देश का अब तक का सबसे बड़ा स्कूल हैकाथॉन है, जिसमें कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को जोड़ा

जा रहा है। इस पहल के तहत 1.5 लाख स्कूलों के एक करोड़ से अधिक छात्र मिलकर नए विचारों, डिजाइन और प्रोटोटाइप तैयार करेंगे।

चार मुख्य थीम पर काम करेंगे छात्र

विद्यार्थियों को चार राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर प्रोजेक्ट बनाने होंगे। इसमें आत्मनिर्भर भारत- स्वावलंबी तकनीक और समाधान विकसित करना, स्वदेशी- देशी विचारों और नवाचारों को बढ़ावा देना। वोकल फॉर लोकल- स्थानीय उत्पादों, कला और संसाधनों को प्रोत्साहन देना। समृद्धि - सतत विकास और समृद्धि के मार्ग बनाना शामिल है।

क्या है कार्यक्रम की रूपरेखा?

यह बिल्डाथॉन 23 सितंबर को लॉन्च हुआ था।

इसमें पंजीकरण की अंतिम तिथि- 6 अक्तूबर, वहीं इसका लाइव बिल्डाथॉन 13 अक्तूबर को होगा। वहीं विजेताओं की घोषणा दिसंबर महीने में की जाएगी इस दौरान छात्र टीमों में मिलकर अपने विचारों को मूर्त रूप देंगे और वास्तविक जीवन की समस्याओं के समाधान प्रस्तुत करेंगे।

जुबीन गर्ग मौत मामला: 10 अक्टूबर को खुलेगा जहर का राज: सीएम हिमंत सरमा

गुहावटी

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार को गायक जुबीन गर्ग के विसरा नमूने की रिपोर्ट नई दिल्ली की केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) से 10 अक्टूबर को प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट से यह पता चलेगा कि उन्हें मारने के

लिए जहर का इस्तेमाल किया गया था या नहीं। साथ ही सीएम सरमा ने कहा कि हमने न्यायिक समिति की निगरानी में जांच तेज कर दी है और विसरा नमूने की जांच की रिपोर्ट से हमें मौत के बारे में स्पष्ट तस्वीर मिल जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शेखर ज्योति स्वयं इस मामले में आरोपियों में से एक हैं और हो सकता है कि वह दूसरों पर आरोप लगाकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हों।

एमपी में कफ सिरप कांड के बाद ताबड़तोड़ एक्शन

जबलपुर के नौदराब्रिज स्थित कटारिया फार्मा को जिला प्रशासन ने सील कर दिया, सैंपल को भेजा गया लैब

जबलपुर

जबलपुर के नौदराब्रिज स्थित कटारिया फार्मा को सील किए जाने की कार्रवाई रविवार दोपहर को आरंभ हुई। जिला प्रशासन कि इस कार्रवाई में क्षेत्रीय ओमती थाना और औषधि विभाग से जुड़े अधिकारी भी शामिल थे। खबर लिखे जाने तक यह प्रक्रिया चल रही है। छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से जिन बच्चों की मौत हुई है वह दवा यहीं से सप्लाई हुई थी गौरतलब है कि कटारिया फार्मा को ऐसे समय सील किया जा रहा है जबकि सोमवार को मुख्यमंत्री का नगर दौरा प्रस्तावित है।

सैंपल को भेजा गया लैब

बताया जाता है कि औषधि निरीक्षक द्वारा कटारिया फार्मा का निरीक्षण कर कोल्ड्रिफ सीरप के सैंपल लेकर प्रयोगशाला भेजे गए हैं। निरीक्षण के दौरान कटारिया फार्मा पर उपलब्ध कोल्ड्रिफ के शेष स्टॉक की खरीदी बिक्री को तत्काल प्रभाव से बंद करवा दिया गया था।

इसके साथ ही इस फर्म द्वारा जहां दवाई सप्लाई की गई थी उन फर्मों से भी इस दवाइयों के क्रय विक्रय को पूर्णतः प्रतिबंध करवा दिया गया था। सैंपल की रिपोर्ट के आधार पर आगामी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।महत्वपूर्ण है कि पूर्व में औषधि विभाग कटारिया फार्मा में रखें 50 यूनिट फ्रीज कर चुकी है और 16 को सेंपल के तौर पर परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजा गया है। दवाओं की जांच सम्बन्धी रिपोर्ट ड्रग टेस्टिंग लेबोरेट्री तमिलनाडु की रिपोर्ट में डाई इथिलीन ग्लाइकोल 48.6 प्रतिशत पाया गया है। शासकीय औषधीय प्रयोगशाला से शनिवार को प्राप्त हुई रिपोर्ट में 46.8 प्रतिशत डाई इथिलीन ग्लाइकोल पाया गया है। जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जिसकी वजह से किडनी फैल हो सकती है। और बच्चो की मौत हो रही है। डाईथिलीन ग्लाइकोल सीरप में प्रतिबंधित पदार्ध है। लिहाज ऐसे सीरप बनाने वाली कंपनी और चिकित्सक डॉक्टर प्रवीण सोनी पर केस दर्ज किया गया है।

कफ सिरप से मौत के मामले में हुई कार्रवाई

नई दिल्ली

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कोल्ड्रिफ कफ सिरप के सेवन से 14 बच्चों की जान चली गई। इस घटना ने देश भर में लोगों को चिंता में डाल दिया है। केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि राजस्थान, महाराष्ट्र में भी इस सिरप से बच्चों के बीमार होने की खबरें सामने आई है। इस घटना के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप समेत कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स के सभी प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया है। वहीं, कफ सिरप लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है और सस्पेंड भी कर दिया गया है।

कोल्ड्रिफ सिरप लिखने वाले डॉक्टर हुए गिरफ्तार

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में इस कफ सिरप के कारण हुई बच्चों की मौत के बाद प्रशासन ने एक्शन लिया है। मध्य प्रदेश पुलिस ने डॉक्टर प्रवीण सोनी को छिंदवाड़ा के परासिया से गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि डॉक्टर प्रवीण सोनी परासिया के जाने-माने बाल रोग विशेषज्ञ हैं। उन्होंने इस सिरप को उन बच्चों को देने का सुझाव दिया था, जो सर्दी खांसी से पीड़ित थे। हालांकि, कोल्ड्रिफ सिरप के सेवन कई बच्चों की जान चली गई।

आशंका जताई जा रही है कि इस सिरप के सेवन के बाद बच्चों की किडनी फेल हो गई, जिससे उनकी जान चली गई। कोल्ड्रिफ कफ सिरप से मौत मामले में मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है।

पदस्थ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रवीण सोनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया

राज्य सरकार ने छिंदवाड़ा के चिकित्सक प्रवीण सोनी को निलंबित भी कर दिया है। राज्य के सीएम ने इस बात की जानकारी दी है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर छिंदवाड़ा जिले के परासिया में पदस्थ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रवीण सोनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। शिशुओं के उपचार में लापरवाही बरतने के आरोप में उन्हें निलंबित किया गया है। निलंबन के बाद उन्हें क्षेत्रीय कार्यालय स्वास्थ्य सेवाएं, जबलपुर में अटैच कर दिया गया है।

105 बीएनएस, 276 बीएनएस और 27 (ए) ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

शिशु गृह में बच्चे की मौत का जिम्मेदार कौन? 3 सदस्यीय कमेटी करेगी जांच

नई दिल्ली

आंध्र प्रदेश में एक स्थानीय शिशु गृह में 18 महीने के बच्चे की मौत की जांच 3 सदस्यीय समिति को देने को फैसला किया गया है। आरोप है कि इस बच्चे की मौत की सूचना अधिकारियों को देने में लापरवाही की गई और बिना उचित प्रक्रिया का पालन किए उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। कल्याणदुर्ग निवासी एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया था। यह शिशु कथित तौर पर बेहद कम वजन का पैदा हुआ था। उसकी मां ने बच्चे के जन्म के तुरंत बाद ही आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए उसे शिशु गृह को सौंप दिया था। 30 सितंबर से यह बच्चा शिशु गृह के संरक्षण में था और यहीं उसकी देखभाल की जा रही थी।

वॉट्सएप पर दी गई मौत की सूचना

दशहरे के दिन बच्चे को दस्त होने लगे और इसके पश्चात उसकी मौत हो गई। कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगा। लेकिन विवाद सिर्फ यही नहीं थमा। शिशु गृह के अधिकारियों ने जिला कलेक्टर और आईसीडीएस परियोजना अधिकारी वॉट्सएप पर बच्चे की मौत की सूचना दी और अगली ही सुबह उसके शव को दफना दिया। यह प्रोटोकॉल का घोर उल्लंघन था। अनंतपुर के जिला कलेक्टर ने तुरंत जांच के आदेश दिए। बच्चे की मौत के कारण और उसके बाद के घटनाक्रम पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। बताया ये भी जा रहा है कि बच्चे की मौत से पहले उसे सरकारी सामान्य अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन उसकी हालत स्थित बताते हुए डॉक्टरों ने उसे वापस भेज दिया था।

कलाईनार यूनिवर्सिटी बिल पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची स्टालिन सरकार

नई दिल्ली

तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल आरएन रवि के बीच कलाईनार विश्वविद्यालय को लेकर जारी विवाद बढ़ता ही रहा है। ऐसे में अब स्टालिन सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। याचिका में राज्य सरकार ने राज्यपाल आरएन रवि द्वारा कलाईनार यूनिवर्सिटी बिल 2025 को राष्ट्रपति के पास भेजने के फैसले को असंवैधानिक और अवैध बताया गया है। राज्य सरकार का कहना है कि राज्यपाल ने इस बिल पर कैबिनेट की सलाह को नजरअंदाज कर, उसे राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज दिया है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 200 का उल्लंघन है। इस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानसभा द्वारा पारित बिलों पर कैबिनेट की सलाह के अनुसार निर्णय लेना होता है।

समझिए क्या है कलाईनार यूनिवर्सिटी बिल?

बता दें कि यह बिल तमिलनाडु विधानसभा में अप्रैल 2025 में पारित हुआ था। इसमें भरतिदासन यूनिवर्सिटी को दो भागों में बांटकर कलाईनार यूनिवर्सिटी की स्थापना करने का प्रस्ताव है। यह यूनिवर्सिटी कुंभकोणम में बनेगी और इसका उद्देश्य अरियालुर, नागपट्टिनम, तंजावुर और तिरुवरूर जिलों के छात्रों को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। इस यूनिवर्सिटी का नाम पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके नेता एम करुणानिधि के नाम पर रखा गया है, जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन के पिता हैं। बिल में प्रावधान है कि मुख्यमंत्री स्टालिन यूनिवर्सिटी के पहले कुलपति होंगे।

दूसरा बिल भी राष्ट्रपति के पास भेजा गया

इतना ही नहीं मामले में राज्यपाल ने दूसरा बिल भी राष्ट्रपति के पास भेजा है, जो कि तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट में बदलाव से जुड़ा है। इस बदलाव से राज्य सरकार को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति और हटाने का अधिकार मिल जाता।

समझिए क्या है सरकार की मांग?

गौरतलब है कि इस पूरे मामले में राज्य सरकार की मांग है कि राज्यपाल का फैसला अवैध और असंवैधानिक घोषित किया जाए। साथ ही राज्यपाल को निर्देश दिया जाए कि वो अनुच्छेद 200 के तहत कैबिनेट की सलाह के अनुसार ही कार्रवाई करें।

भविष्य के युद्धों से निपटने के लिए सेना की नई रुद्र ब्रिगेड का गठन: सेना प्रमुख

नई दिल्ली

ऑपरेशन सिंदूर के बाद सैन्य आधुनिकीकरण और एकीकृत थियेटर योजना की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सेना ने अपनी एकीकृत नई रुद्र ब्रिगेड का गठन कर दिया। सेना की उत्तरी कमान ने एक्स पर इसकी घोषणा की। इस ब्रिगेड में इंफैंट्री, मेकेनाइज्ड इंफैंट्री, आर्मर्ड यूनिट, आर्टिलरी, स्पेशल फोर्स, अनमैन्ड एरियल सिस्टम और ऐसे ही युद्धक कंपोनेंट शामिल किए गए हैं। इस ब्रिगेड को लॉजिस्टिक या कांबैट सपोर्ट जैसे विशेष कार्यों के लिए तैयार किया गया है। जुलाई में आर्मी चीफ ने की थी नई ब्रिगेड की घोषणा

बता दें कि 26वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर इस साल 26 जुलाई को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेना के लिए नई रुद्र ब्रिगेड के गठन की घोषणा की थी। सेना की उत्तरी कमान ने अपनी पोस्ट में लिखा कि भारतीय सेना क्षमता विकास और भविष्य के युद्धों के लिए तैयारी पर अपनी ध्यान निरंतर बनाए हुए है।

रक्षा विश्लेषकों का क्या कहना है?

रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि ब्रिगेड में विशेष बलों और मानवरहित प्रणालियों को शामिल करना परंपरागत ताकत को उभरती हुई तकनीक को जोड़ने की दिशा में एक कदम है। उम्मीद है कि यह नया गठन भविष्य के युद्धों के लिए भारत की तैयारी सुनिश्चित करेगा और साथ ही सीमाओं पर मजबूत संदेश भी भेजेगा।

कर्नाटक: जातीय जनगणना में नहीं पूछे जाएंगे निजी सवाल: डिप्टी सीएम डीके

बेंगलुरु

देश में जातीय जनगणना की मांग काफी समय से उठ रही थी। केंद्र सरकार ने भी जातीय जनगणना करवाने की घोषणा की थी। वहीं, बिहार के बाद कर्नाटक सरकार ने राज्य स्तर पर सामाजिक और आर्थिक सर्वे शुरू कर दिया है, जिसे जातीय जनगणना का नाम दिया जा रहा है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का कहना है कि सर्वे में कोई भी निजी सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों से सर्वे में शामिल होने का अनुरोध किया है।

डिप्टी सीएम ने क्या कहा?

कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सामाजिक और आर्थिक सर्वे करवाने के लिए कहा गया है। यह सर्वे 22 सितंबर से शुरू हो गया है, जो 7 अक्तूबर तक चलेगा। वहीं, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का इसपर कहना है, "कोई कुछ भी कहे, यह सर्वे होकर रहेगा। अदालत ने कहा है कि यह सर्वे स्वैच्छिक होगा। लोग जिन सवालों का जवाब देना चाहेंगे, दे सकेंगे और उन्हें जिसका जवाब नहीं देना होगा, उसके लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा।"डीके शिवकुमार ने कहा- मैंने अधिकारियों को पहले से कह दिया है कि बेंगलुरु में लोगों से यह न पूछें कि उनके पास कितनी मुर्गियां, भेड़ें और बकरियां हैं? उनके पास कितना सोना है? यह उनके निजी मामले हैं। डीके शिवकुमार के अनुसार, "कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग एक स्वतंत्र कमीशन है। वो क्या सवाल पूछेंगे, मुझे नहीं पता। मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपील करता हूं कि इस सर्वे में हिस्सा जरूर लें।" कर्नाटक हाईकोर्ट ने पिछले महीने सर्वे रोकने से साफ इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को आदेश दिया था कि जो लोग इस सर्वे में हिस्सा लेना चाहते हैं, वो ले सकते हैं।

शिवराज सिंह चौहान की 'खास उड़ान', फ्लाइट के को-पायलट को देखकर रह गए दंग

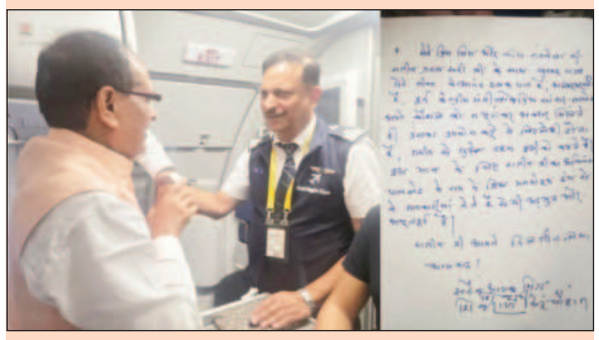

शिवराज सिंह चौहान की फ्लाइट में को-पायलट बने बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी

रूडी ने यात्रियों को दिलचस्प अंदाज में बताया सफर का दृश्य

नई दिल्ली

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए पटना से दिल्ली की फ्लाइट यात्रा बेहद यादगार बन गई। वजह न कोई खराब मौसम थी और न देरी, बल्कि इस उड़ान के को-पायलट थे भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी। शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना यह अनुभव साझा करते हुए लिखा, "रूडी जी की मिलनसारिता, बातचीत का अंदाज और यात्रियों से जुड़ने का तरीका इस सफर को अविस्मरणीय बना गया।"

रूडी की तारीफ में शिवराज के शब्द

केंद्रीय मंत्री ने लिखा, "राजीव जी आज आपने हमारा दिल जीत लिया...पटना से दिल्ली की यह उड़ान मेरे लिए अविस्मरणीय रही, क्योंकि इसके को-पायलट मेरे प्रिय मित्र, वरिष्ठ नेता और छपरा से सांसद राजीव प्रताप रूडी थे।" उन्होंने दोनों की साथ ली गई तस्वीरें और एक हैंडरिटन नोट भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने रूडी की तारीफ की।

राजीव प्रताप रूडी का अनोखा अंदाज

उड़ान के दौरान राजीव प्रताप रूडी ने यात्रियों के लिए एक घोषणा भी की थी। उन्होंने कहा, "आज पटना के आसमान में बादल छाए हैं और कल से बारिश जारी है। इन बादलों और हल्की फुहारों के बीच हम दिल्ली की ओर रवाना हो रहे हैं। रास्ते में वाराणसी ऊपर से दिखेगा, बाईं ओर प्रयागराज और दाईं ओर लखनऊ। गंगा-यमुना के दर्शन करते हुए दिल्ली पहुंचेंगे और अगर उतरते वक्त बादल न हो तो नोएडा की ऊंची इमारतों की रोशनी भी दिखेगी।" बता दें, राजीव प्रताप रूडी बिहार से चार बार सांसद रह चुके हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं।

भारत और कनाडा के बीच बढ़ती नजदीकी से खालिस्तानी बौखलाए

नई दिल्ली

भारत और कनाडा के बीच सुरक्षा सहयोग मजबूत होने के साथ ही खालिस्तानियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। द्विपक्षीय संबंधों को फिर से मजबूती प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके कनाडाई समकक्ष मार्क कार्नी की मुलाकात के बाद मिली। इस मुलाकात के बाद दोनों देशों के अधिकारियों के बीच बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) और उनके कनाडाई समकक्ष नथाली ड्रोइन के बीच एक उच्च-स्तरीय बैठक हुई। आपसी रिश्तों के फिर से मजबूत होने से कनाडा ने लारेंस बिश्नोई गिरोह को एक आतंकी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया।

गिरोह ने भय का माहौल पैदा किया

गिरोह को आतंकी संगठन बताते हुए कनाडा ने कहा कि इस गिरोह ने भय का माहौल पैदा किया है। भारत के लिए यह फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस गिरोह से खालिस्तानी तत्व जुड़े हुए हैं। एनआइए गैंगस्टर-आतंकी गठजोड़ मामले की जांच कर रही है। जांच के दौरान एनआइए ने पाया है कि यही गिरोह खालिस्तानियों के इशारे पर धन जुटा रहा है।

विभिन्न दलों के नेताओं से पहली बार मिलेंगे उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन

नई दिल्ली

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सात अक्टूबर को संसद परिसर में विभिन्न दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद नेताओं के साथ ये उनकी पहली मुलाकात होगी। उपराष्ट्रपति से मुलाकात के लिए जिन नेताओं को आमंत्रित किया गया है उनमें भाजपा अध्यक्ष और सदन के नेता जेपी नड्डा, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजु, राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन प्रमुख रूप से शामिल हैं। इसके अलावा बैठक में तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, आप, राजद, बीजद, अन्ना द्रमुक, माकपा, भाकपा, राकांपा और जद(स) को भी आमंत्रित किया गया है। शरद पवार, एचडी देवेगौड़ा, एम थंबीदुरई, डेरेक ओ ब्रायन, तिरुचि शिवा, संजय सिंह, सुभाष चंद्र बोस पिल्ली, सस्मित पात्रा, प्रेम चंद गुप्ता, संजय राउत, राम गोपाल यादव आदि से मिलेंगे।

देश में अमीरी और गरीबी की खाई को बढ़ा रही सरकार: कांग्रेस

नई दिल्ली

कांग्रेस ने रविवार को सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र अमीरी और गरीबी की खाई को बढ़ा रहा है। पार्टी ने कहा कि यह सिर्फ अर्थव्यवस्था के लिए समस्या नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा पर सीधा हमला है।

> सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण देश का पैसा कुछ खास लोगों के बीच केंद्रित हो गया है। इसके कारण हमारे देश में भारी आर्थिक असमानता पैदा हुई है। यह असमानता व्यापक सामाजिक असुरक्षा और असंतोष को जन्म दे रही है।
>
> - जयराम रमेश, महासचिव, कांग्रेस

जयराम रमेश बोले- लाखों भारतीय अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे

कांग्रेस महासचिव व संचार प्रभारी जयराम रमेश ने एक्स पर एक मीडिया रिपोर्ट साझा की। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत अब अरबपतियों का नया केंद्र बनता जा रहा है और देश में अमीर लोगों की संख्या साल दर साल तेजी से बढ़ रही है। रमेश ने एक्स पर हिंदी में लिखे एक पोस्ट में कहा, "एक के बाद एक रिपोर्ट भारत में धन के एक खास वर्ग के बारे में सीमित होने की चेतावनी दी जा रही है। जहां लाखों भारतीय अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं सिर्फ 1,687 लोगों के पास देश की आधी संपत्ति है।"

उन्होंने कहा, "मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण देश का पैसा कुछ खास लोगों के बीच केंद्रित हो गया है। इसके कारण हमारे देश में भारी आर्थिक असमानता पैदा हुई है। यह असमानता व्यापक सामाजिक असुरक्षा और असंतोष को जन्म दे रही है।" उन्होंने कहा कि अन्य देशों में हाल की घटनाओं से पता चला है कि यही चरम आर्थिक असमानता और अपंग लोकतांत्रिक संस्थाएं राजनीतिक अराजकता की उत्प्रेरक बनी हैं।

सत्ता के गठजोड़ के कारण कुछ उद्योगपति और अधिक अमीर होते जा रहे: कांग्रेस

रमेश ने कहा कि यह सरकार भारत को उसी रास्ते पर धकेल रही है। उन्होंने आरोप लगाया, "सत्ता के गठजोड़ के कारण कुछ उद्योगपति और अधिक अमीर होते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की नीतियां पूरी तरह से उनके कुछ उद्योगपति मित्रों के लाभ पर केंद्रित हैं।" रमेश ने दावा किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ एमएसएमई क्षेत्र अभूतपूर्व दबाव में है। यह दबाव न केवल घरेलू नीतियों का बल्कि विदेश नीति के मोर्चे पर सरकार की विफलताओं का भी परिणाम है। रमेश ने कहा, "आम लोगों के लिए कमाई के अवसर कम होते जा रहे हैं। मुद्रास्फीति इतनी बढ़ गई है कि नौकरीपेशा लोग भी बचत के बजाय कर्ज के बोझ तले दब रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं कमजोर होती जा रही हैं।" उन्होंने कहा कि मनरेगा जैसी सफल योजनाएं, जिसने लाखों लोगों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान की, अब मजदूरी संकट से जूझ रही हैं।

बीड के सरकारी अस्पताल में जुड़वा बच्चों की जन्मदर में अप्रत्याशित बढ़ोतरी

मुंबई

आमतौर पर जुड़वां बच्चों के जन्म को पहले एक दुर्लभ घटना माना जाता था लेकिन महाराष्ट्र के बीड जिले के सिविल अस्पताल के लिए यह घटना एक सामान्य सी बात हो गई है। बीड के इस सरकारी अस्पताल में पिछले नौ महीनों में 42 जुड़वां बच्चों का जन्म हुआ है। लगातार पैदा हो रहे जुड़वां बच्चे अस्पताल के लिए एक गर्व का विषय बन गया है, क्योंकि प्रसूति वार्ड के कर्मचारियों ने सिजेरियन और प्राकृतिक प्रसव, दोनों का सफलतापूर्वक कर रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार, सहायक प्रजनन तकनीक (एआरटी), जिसमें इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) शामिल है, और पारिवारिक इतिहास जुड़वां बच्चों के जन्म में वृद्धि का कारण बन रहे हैं। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि 30 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं में जुड़वां बच्चे होने की संभावना में मामूली वृद्धि हुई है। बीड सिविल अस्पताल के रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर (आरएमओ) डॉ एलआर तंदले ने कहा, पिछले कुछ वर्षों में जुड़वां और तीन बच्चों के जन्म की दर निश्चित रूप से बढ़ी है, और पिछले नौ महीनों में हमारे यहां 42 जुड़वां बच्चे पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल में एक विशेष चिकित्सा टीम है जो प्रसव के दौरान और उसके बाद माताओं तथा शिशुओं की व्यापक देखभाल करने के लिए समर्पित है।

हर कारीगर को आत्मनिर्भर बनाना हमारा संकल्प: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रविवार को नरेला के आदर्श रामलीला मैदान में प्रजापति (कुम्हार) महाकुंभ में सम्मिलित होकर समाज के लोगों से संवाद किया

सीएम रेखा गुप्ता प्रजापति महाकुंभ में शामिल हुई

सरकार इस समाज की सृजनशील शक्ति को सशक्त करने के लिए पूर्णत: प्रतिबद्ध

नई दिल्ली
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रविवार को नरेला के आदर्श रामलीला मैदान में प्रजापति (कुम्हार) महाकुंभ में सम्मिलित होकर समाज के लोगों से संवाद किया। इस अवसर पर सांसद योगेन्द्र चांदोलिया, विधायक राज करण खत्री सहित प्रजापति समाज के अनेक लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार इस समाज की सृजनशील शक्ति को सशक्त करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, प्रशिक्षण, बाजार से जुड़ाव और आधुनिक तकनीक के सहयोग से हर कुम्हार, हर कारीगर को आत्मनिर्भर बनाना हमारा संकल्प है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी और वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित होकर, हम दिल्ली के हर बाजार और हर घर तक स्थानीय हस्तनिर्मित वस्तुओं को प्रमोट कर रहे हैं ताकि मिट्टी के कलाकारों की मेहनत का सम्मान हो और भारत का कौशल, भारत की पहचान बने।

मांडविया ने फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के 43वें संस्करण का नेतृत्व किया

नई दिल्ली
केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने रविवार सुबह राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में विश्व शिक्षक दिवस पर फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के 43वें संस्करण का नेतृत्व किया। यह कार्यक्रम देश भर में 10,000 से अधिक स्थानों पर एक साथ आयोजित किया गया। दिल्ली भर से शिक्षकों, एथलीट्स, फिटनेस इन्फ्लुएंसर और युवाओं सहित 1,000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया। भारतीय हॉकी खिलाड़ी अभिषेक नैन, शतरंज की दिग्गज खिलाड़ी तानिया सचदेव, उभरते हुए भाला फेंक स्टार सचिन यादव और भारत के पुशअप मैन कहे जाने वाले रोहताश चौधरी भी शामिल थे। डॉ. मांडविया ने इस पहल को एक सच्चा राष्ट्रव्यापी आंदोलन बताया।

दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने 5.5 करोड़ के विकास कार्यों का पंखा रोड क्षेत्र में किया शिलान्यास

नई दिल्ली
दिल्ली के शिक्षा मंत्री एवं जनकपुरी के विधायक आशीष सूद ने रविवार को 5.5 करोड़ रुपये की लागत से पंखा रोड क्षेत्र के पुनर्विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस परियोजना के अंतर्गत नई आरसीसी ड्रेन का निर्माण, ग्रिट प्लास्टर एवम आयरन ग्रिल के साथ टो वाल का निर्माण, फुटपाथ का निर्माण, सड़क के दोनों और स्ट्रीट लाइट लगाने का काम तथा सर्विस लेन में सौंदर्य करण और हरियाली के कामों के साथ-साथ पूरे क्षेत्र की सफाई, सौंदर्यीकरण और लैंडस्केपिंग के अनेक कार्यों का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत सहरावत के साथ साथ जनकपुरी के कई ब्लॉकों के आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधि, स्थानीय निवासी तथा आस पास के बाजारों के दुकानदार भी उपस्थिति रहे। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने बताया कि दशकों तक जनकपुरी के निवासियों की आवाज को अनसुना किया गया लेकिन अब बदलाव की हवा बह रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में हम दिल्ली के जनकपुरी क्षेत्र के निवासियों की न सिर्फ समस्याएं सुन रहे हैं बल्कि उनके ठोस समाधान के लिए भी दिन-रात कई स्तरों पर काम भी किया जा रहा है अब पूरे जनकपुरी में विकास की हवा बह रही है। उन्होंने बताया कि आज इसी कड़ी में जनकपुरी के पंखा रोड की में कई विकास कार्यों की शुरूआत की गई है।

नलों से साफ पानी की जगह आ रहा सीवर का गंदा और बदबूदार पानी

नई दिल्ली
पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में दूषित पेयजल की सप्लाई हो रही है, जिसे पीकर लोग बीमार हो रहे हैं। ऐसे में लोगों को अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए बाजार से पानी खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। यहां तक कि खाना पकाना, बर्तन धोना, स्नान करना और शौच जाने तक के लिए उन्हें परेशान होना पड़ रहा है। दरअसल, लक्ष्मी नगर स्थित डी-ब्लॉक और मयूर विहार फेस-1 स्थित पॉकेट-2, में यह समस्या बीते कई महीनों से बनी हुई है। लोगों का कहना है कि उनके घरों में नलों से साफ पानी की जगह सीवर का गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है। इससे उनकी दैनिक दिनचर्या प्रभावित हो रही है। उनका दावा है कि सीवर युक्त पानी पीकर क्षेत्र के लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है जिसकी वजह से वह बीमार पड़ रहे हैं। इसके अलावा दूषित पानी के इस्तेमाल से जल जनित बीमारियों, जैसे पेट दर्द, उल्टी, दस्त और त्वचा संबंधी एलर्जी का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। उनका कहना है कि इलाके में जो पानी की पाइप लाइन लगी हुई है वह सीवर वाले पाइपलाइन के साथ मिली हुई है। ऐसे में पानी की पाइपलाइन में लीकेज होने से दोनों आपस में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से घरों में सीवर वाला पानी आ रहा है। लोगों ने बताया कि यह समस्या दशकों पुरानी है। इलाके में जो पाइपलाइन और सीवर डाले गए हैं, वह अव्यवस्थित और जर्जर सख्त जरूरत है। वहीं, दूषित जल की आपूर्ति से लोगों को पीने और खाना पकाने तक के लिए मजबूरन महंगे पानी के जार या बोतलें खरीदनी पड़ रही हैं।

ट्रेड फेयर में उद्योगों में हुए बदलाव को दिखाएगा बड़ा पैवेलियन

नई दिल्ली
दिल्ली सरकार इस बार इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (आईआईटीएफ) में बड़ा पैवेलियन बनाकर राजधानी में व्यापार को आसान बनाने के लिए किए सुधारों को प्रदर्शित करने की योजना बना रही है। तैयारियों को शुरू करते हुए सरकार ने दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (डीएसआईआईडीसी) को यह जिम्मेदारी सौंपी है। डीएसआईआईडीसी ने भारत मंडपम में पैवेलियन बनाने का टेंडर जारी किया है, जिससे डिजाइन एजेंसी की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

बिश्नोई गैंग के बुरे दिन: सुरक्षा एजेंसियों का दावा- अलग हुए गोल्डी बराड़ और काला जठेड़ी

नई दिल्ली
अपराध की दुनिया में एकछत्र राज करने वाले लारेंस बिश्नोई व उसके गैंग के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। सुरक्षा एजेंसियों की मानें तो लारेंस गैंग का दाहिना हाथ कहे जाने वाले कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ और काला जठेड़ी भी अलग हो गए हैं। ये लारेंस के लिए बहुत बड़ा झटका है। राजस्थान का गैंगस्टर रोहित गोदारा भी लारेंस गैंग से अलग हो चुका है। अधिकारियों की मानें तो इस समय लारेंस बिश्नोई अमेरिका में बैठे भाई अनमोल के साथ अकेला रह गया है। कनाड़ा सरकार ने हाल ही में लारेंस के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। कनाडा सरकार ने बिश्नोई गैंग को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। बिश्नोई गैंग पर कनाडा में खास समुदाय को निशाना बनाकर डर और धमकी का माहौल बनाने का आरोप है। इसे देखते हुए कनाडा की पब्लिक सेफ्टी मिनिस्ट्री की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि बिश्नोई गैंग एक इंटरनेशनल टेरेरिस्ट गैंग है जो हिंसा दहशतगर्दी और डराने धमकाने का काम करता है। ऐसे में बिश्नोई गैंग को आतंकी संगठन घोषित करने के बाद कनाडा की सरकार को उसके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई करने की छूट मिलेगी। लारेंस का खास माने जाने वाला रोहित गोदारा भी उससे अलग हो चुका है। बरेली, यूपी में फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामले में लारेंस और रोहित गोदारा के बीच दरार खुलकर सामने आ चुकी है। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ एक्स पर खुलकर लिख चुके हैं। अब गोल्डी बराड़ भी लारेंस से अलग हो चुका हैं।

लारेंस इनके नाम का कर रहा था इस्तेमाल-
देश की सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों का कहना है कि जेल में निरुद्ध लारेंस बिश्नोई गोल्डी बराड़, काला जठेड़ी, रोहित गोदारा आदि के नाम का उगाही के लिए इस्तेमाल कर रहा था और इन्हीं से वारदातें करवा रहा था। इसे देखते हुए ये गैंगस्टर लारेंस से अलग हुए हैं। अब ये अपने ही साम्राज्य चलाना चाहते है। एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि गोल्डी बराड़ काला जठेड़ी व अलग गैंगस्टर भी अलग हो चुके हैं।

इस समय देश विरोधी काम करने वाले खालिस्तानियों से जुड़ गया है। गोल्डी बराड़ समेत कुछ गैंगस्टरों का नाम ड्रग्स मामले में सामने आ चुका है। इसको लेकर इनका व लारेंस का मनमुटाव हो गया।
छोटे भाई अनमोल को लेकर भी लारेंस व गोल्डी के बीच तकरार पैदा हो गई थी। जेल में बंद 32 वर्षीय गैंगस्टर लॉरेंस ने 2010 में पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र रहते हुए अपराध की दुनिया में कदम रखा था। उसने यूनिवर्सिटी में छात्रसंघ चुनाव के दौरान एक प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार पर गोलीबारी की थी।

स्वामी चैतन्यानंद: पुराने पाप भी सामने आए, बताता था 'मिनिस्टर ऑफ स्टेट

नई दिल्ली
दिल्ली के वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट-रिसर्च में 17 छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थसारथी की असलियत अब परत-दर-परत सामने आ रही है। खुद को साधु बताने वाला यह बाबा दरअसल फर्जी दस्तावेजों और नकली पहचान के सहारे वर्षों से ठगी और शोषण का खेल खेल रहा था। जांच में खुलासा हुआ है कि बाबा के पास से प्रधानमंत्री कार्यालय का फर्जी पहचान-पत्र मिला है। यही नहीं, बाबा ने फरीदाबाद के एक नामी स्कूल को पत्र भेजकर खुद को 'मिनिस्टर ऑफ स्टेट' बताया था। पुलिस के हाथ ऐसे कई फोटो भी लगे हैं जिनमें बाबा खुद को देश के बड़े नेताओं और संतों के साथ जोड़ने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। दरअसल, ये तस्वीरें या तो फोटोशॉप की गई हैं या फिर झूठे दावों के सहारे खिंचवाई गई थीं। बाबा के पास से यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री भी मिली, लेकिन जब जांच शिकागो यूनिवर्सिटी तक पहुंची तो वहां से साफ जवाब मिला कि ऐसी कोई डिग्री हमने कभी जारी नहीं की। यानी बाबा की पढ़ाई-लिखाई भी सिर्फ एक दिखावा थी। बाबा अपने विजिटिंग कार्ड पर भी खुद को शिकागो यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ लिखवाकर लोगों को गुमराह करता रहा।

यमुना के तटों पर प्राकृतिक विरासत को मिलेगा नया जीवन

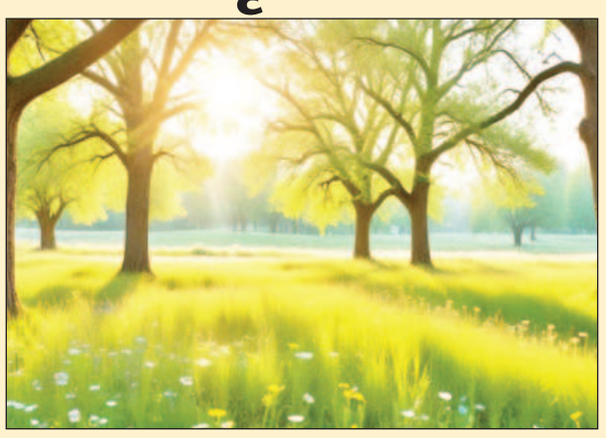

नई दिल्ली
दिल्ली की प्राकृतिक विरासत को संजोने और यमुना के तटों को नया जीवन देने के लिए डीडीए ने 61.56 लाख की तीन नई परियोजनाएं शुरू की हैं। डीडीए यमुना के बाढ़ क्षेत्र और खास तौर पर आईटीओ ब्रिज से एनएच-24 के बीच के क्षेत्र में अमृत बायोडायवर्सिटी पार्क को फिर से विकसित करेगा। यह परियोजना सीधे तौर पर दिल्ली की प्राकृतिक विरासत को संवारने और शहर को अधिक हरियाली देने के लिए है। इसमें यमुना किनारे आर्द्रभूमि के साथ घास के मैदान, दुर्लभ और स्थानिक पौधों वाले मैदानी वन विकसित करने का लक्ष्य है जो दिल्ली की जैव विविधता को मजबूत करेंगे। डीडीए के विवेक विहार हॉर्टिकल्चर डिवीजन ने कुल 61,56,101 रुपये की तीन प्रमुख बागवानी परियोजनाओं के ऑनलाइन टेंडर जारी किए हैं। 13 अक्तूबर को दोपहर तीन बजे तक टेंडर भरे जाएंगे और 14 अक्तूबर को इनकी तकनीकी बोलियां खोली जाएंगी।

अमृत बायोडायवर्सिटी पार्क होगा आकर्षण
डीडीए ने कुल तीन काम के टेंडर जारी किए हैं जिसमें दो परियोजनाएं सीधे यमुना के बाढ़ क्षेत्र में पूर्वी-पश्चिमी तट अमृत बायोडायवर्सिटी पार्क के विकास से जुड़ी हैं। इसमें आईटीओ-बैराज से एनएच-24 तक अमृत बायोडायवर्सिटी पार्क को हरियाली से भरपूर आकर्षक बनाने की योजना है। एनएच-24 से सीडब्ल्यूजी फ्लैट्स के बीच बड़े पैमाने पर हरित वन क्षेत्र बढ़ाए जाएंगे।
यहां पौधे लगाने के लिए अच्छी मिट्टी, यमुना की रेत, गड्ढों की खुदाई, पॉलीथिन बैग, मौसमी बीज, पौधों के तेजी से विकास के लिए पोषण देने वाले बोन मील, नीम तेल और एनपीके उर्वरक की सप्लाई होगी। इसके लिए कुल 48,94,271 रुपये खर्च किए जाएंगे। इस काम को 90 दिन के भीतर पूरा करने का लक्ष्य है। तीसरी परियोजना के तहत कालिंदी अविरल एक्सटेंशन में नर्सरी विकसित की जाएगी। इसके रखरखाव के लिए डीडीए ने 12,61,830 का बजट रखा है। नर्सरी में गमले, पॉलीथिन बैग और पौधों की सप्लाई होगी। डीडीए ने ठेकेदारों के लिए सख्त नियम रखे हैं। केवल डीडीए में पंजीकृत ठेकेदार ही काम कर सकेगा। डीडीए के अधिकारियों ने कहा कि एलजी वीके सक्सेना बाढ़ क्षेत्र में जैव विविधता विकसित करने को लेकर बेहद गंभीर हैं। वे नियमित रूप से इसकी जानकारी लेते हैं।

टीजीटी शिक्षक के पदों पर बंपर भर्ती! भरे जाएंगे 5300 से अधिक पद

नई दिल्ली
दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी शिक्षक के पदों पर भर्ती के लिए नोटिस जारी किया है। इस भर्ती के तहत गणित, अंग्रेजी, एसएसटी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू समेत विभिन्न विषयों के लिए कुल 5,346 पद भरे जाएंगे। पंजीकरण प्रक्रिया 9 अक्तूबर, 2025 से शुरू होगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पूरी करनी होगी।

ग्रैंड पेरेंट्स डे: 1536 स्कूलों को मिलेंगे 10-10 हजार

नई दिल्ली
शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी एक परिपत्र के अनुसार, दिल्ली सरकार समग्र शिक्षा योजना के तहत प्राथमिक स्तर पर 1,500 से अधिक स्कूलों में दादा-दादी दिवस मनाएगी। इस आयोजन के लिए शिक्षा मंत्रालय के परियोजना अनुमोदन बोर्ड ने 153.6 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया है। इस कार्यक्रम का आयोजन पायलट आधार पर दिल्ली नगर निगम के 1,536 स्कूलों में किया जाएगा।
बयान में कहा गया है कि प्रत्येक स्कूल को पूरे दिन चलने वाले इस कार्यक्रम के संचालन के लिए 10,000 रुपये दिए जाएंगे। इस राशि में लगभग 100 लोगों के लिए जलपान, दादा-दादी के लिए सहभागिता उपहार, दो गतिविधियों के लिए पुरस्कार और अन्य खर्च शामिल होंगे। परिपत्र में उल्लेख किया गया है कि छात्रों को इस समारोह में अपने साथ एक दादा-दादी को लाने की अनुमति होगी। इसमें नृत्य प्रदर्शन, पेपर बैग और फोटो फ्रेम बनाना, साथ ही गुब्बारा रिले दौड़ जैसे खेल शामिल होंगे।सर्कुलर में कहा गया है कि जिला शहरी संसाधन समन्वयक, क्लस्टर संसाधन समन्वयक और स्कूल प्रमुख कार्यक्रम के दौरान शारीरिक रूप से उपस्थित रहेंगे। वे उच्च-रिजॉल्यूशन वाली तस्वीरों और वीडियो के माध्यम से समारोह का दस्तावेजीकरण करें।

अंडरवियर पहनकर अदालत में वर्चुअली पेश हुआ एक शख्स, गिरफ्तार

नई दिल्ली
पुलिस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही अदालती कार्यवाही में बाधा डालने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। वह धूम्रपान और शराब पीते हुए अंडरवियर में अदालत में पेश हुआ था। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि गोकुलपुरी निवासी मोहम्मद इमरान (32) एक हिस्ट्रीशीटर है और उसके खिलाफ दिल्ली भर में लूट, झपटमारी और अन्य अपराधों के 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। तीस हजारी कोर्ट स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंशुल सिंघल की अदालत के रिकॉर्ड कीपर की शिकायत पर 22 सितंबर को मामला दर्ज किया गया था। उत्तर जिला के पुलिस उपायुक्त राजा बंठिया ने बताया कि आरोपी पर आरोप है कि 16 और 17 सितंबर को एक अज्ञात व्यक्ति अकीब अखलाक नाम से अदालत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुआ।

वह धूम्रपान व शराब पीते हुए अंडरवियर में दिखाई दिया। बार-बार जाने के निर्देश देने के बावजूद, वह कथित तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद रहा, जिससे अदालती कार्यवाही में बाधा उत्पन्न हुई। संदिग्ध ने कई फर्जी ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया था और बार-बार अपना ठिकाना बदल रहा था। टीम ने आरोपी को पुराने मुस्तफाबाद के चमन पार्क में ढूंढ निकाला और उसके घर से उसे गिरफ्तार कर लिया।

अनावश्यक एक्स-रे से 20 से कम उम्र वाले मरीजों में 10% बढ़ रहा कैंसर का खतरा

नई दिल्ली
चिकित्सा के क्षेत्र में तकनीक ने क्रांति ला दी है, लेकिन अनावश्यक रेडियोलॉजिकल जांच जैसे एक्स-रे और सीटी स्कैन की बढ़ती प्रवृत्ति मरीजों के लिए खतरा बन रही है। शनिवार को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में आयोजित न्यूरोलॉजिकल सर्जंस सोसाइटी ऑफ इंडिया के दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में डॉ आरएस मित्तल ने यह बातें कही। उन्होंने चेतावनी दी कि बार-बार रेडियोलॉजी जांच से होने वाला विकिरण जोखिम खासकर 20 वर्ष से कम उम्र के मरीजों में कैंसर का खतरा 10 प्रतिशत तक बढ़ा सकता है। इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे छात्र शामिल थे, जिन्हें 15 से 40 साल के अनुभवी डॉक्टरों ने प्रशिक्षण दिया। इस प्रशिक्षण में छात्रों को मरीजों की जांच करना, बीमारी का पता लगाना, बीमारी में इलाज की जरूरतों को समझना, जरूरत न होने पर सर्जरी करने से बचना व एक अच्छा न्यूरो सर्जन बनने का प्रशिक्षण दिया गया। सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष और न्यूरो सर्जन प्रो. आरएस मित्तल ने कहा कि तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता के कारण मैनुअल जांच की कला कमजोर पड़ रही है।

उन्होंने कहा कि जब तक अत्यंत आवश्यक न हो, रेडियोलॉजी जांच से बचना चाहिए। मैनुअल परीक्षण को बढ़ावा देकर न केवल मरीजों के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है, बल्कि अनावश्यक खर्च और जोखिम भी कम किए जा सकते हैं। एनएसएसआई के पूर्व अध्यक्ष प्रो. एमके तिवारी ने बताया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के युग में भी मानवीय विशेषज्ञता की कोई बराबरी नहीं है। एआई हमें दिशा दिखा सकती है, लेकिन मरीज की स्थिति को समझकर सही जांच का चयन केवल प्रशिक्षित सर्जन ही कर सकते हैं।

स्पोंडिलाइटिस का बढ़ता प्रकोप
चिकित्सकों ने बताया कि आजकल युवाओं में स्पोंडिलाइटिस और डिस्क से संबंधित समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। खराब पोस्चर, लंबे समय तक मोबाइल और कंप्यूटर का उपयोग, तनाव और व्यायाम की कमी इसके प्रमुख कारण हैं। विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि नियमित व्यायाम, सही मुद्रा, और संतुलित आहार से इन समस्याओं को रोका जा सकता है।

पूर्वी दिल्ली में दो साल के मासूम की अगवा कर हत्या, पुलिस का दावा- रंजिश में की गई वारदात

नई दिल्ली
उत्तर-पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में शुक्रवार शाम दो साल के मासूम राठौर की अगवा कर हत्या कर दी गई। शनिवार सुबह मासूम का शव सीआरपीएफ कैंप की बाउंडरी वॉल के पास खून से लथपथ पड़ा मिला। इसके सिर पर चोट के निशान मिले हैं। आशंका व्यक्त की जा रही है कि किसी भारी वस्तु से सिर पर वार कर हत्या की गई। खजूरी खास थाना पुलिस ने अपहरण और हत्या का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। खुद अतिरिक्त जिला पुलिस उपायुक्त संदीप लांबा मामले की जांच में जुटे हैं। सीसीटीवी से अहम सुराग मिले हैं। कुछ संदिग्धों की पहचान कर ली गई है।

पुलिस के मुताबिक मासूम राठौर अपने परिवार के साथ खजूरी खास फ्लाईओवर के नीचे रहता था। इनके रिश्तेदार भी आसपास ही रहते हैं। माता-पिता मजदूरी करते हैं। शुक्रवार शाम को अचानक खेलते हुए मासूम गायब हो गया।

संपादक की कलम से

वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में उभर रहा है भारत

विश्व पर्यटन दिवस मानाने का उद्देश्य वैश्विक उद्योग के रूप में पर्यटन के महत्व तथा इसके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। विश्व पर्यटन दिवस मनाने से हमें पर्यटन के हम पर और हमारे आसपास की दुनिया पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलती है। इसमें दुनिया भर में इसके आर्थिक प्रभाव के साथ-साथ नैतिक, नैतिक और पशु कल्याण संबंधी विचार भी शामिल हैं।

संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ) ने विश्व पर्यटन दिवस की स्थापना की। 1980 से हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इसी दिन यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गनाइजेशन के कानूनों को अपनाया गया था। हर साल विश्व पर्यटन दिवस एक विशेष थीम के साथ मनाया जाता है। 2025 का विषय ह्लपर्यटन और हरित निवेशह्व है। यह थीम स्थायी पर्यटन अवसंरचना और परियोजनाओं में निवेश की तत्काल आवश्यकता पर जोर देती है जो समुदायों और अर्थव्यवस्थाओं को समृद्ध बनाने के साथ-साथ हमारे ग्रह की रक्षा में भी मदद करें। हरित निवेश पर्यटन व्यवसायों और यात्रियों दोनों को ऐसे विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करता है जो उनके पर्यावरणीय प्रभाव को कम करें। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दें और सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करें।

विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद (डब्ल्यूटीटीसी) की नवीनतम आर्थिक प्रभाव प्रवृत्ति रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने 2025 में विश्व की सबसे बड़ी पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं में अपने पिछले दसवें स्थान से 8वें स्थान पर एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई है। रिपोर्ट में वैश्विक यात्रा क्षेत्र में भारत के बढ़ते कद पर प्रकाश डाला गया है और अनुमान है कि अगले दशक में यह चौथे स्थान पर होगा। भारत का पर्यटन क्षेत्र 2025 में 231.6 अरब डॉलर का योगदान देगा जो बुनियादी ढाँचे, विपणन और सेवा वितरण में मजबूत वृद्धि और रणनीतिक विकास को दशार्ता है। यह बढ़ता रुझान एक वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को रेखांकित करता है और आर्थिक विस्तार एवं रोजगार को बढ़ावा देने में इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है।

देश के लिए बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की कमाई करने में पर्यटन उद्योग का अच्छा खासा महत्व है। पर्यटन जिसे चिमनी विभिन्न उद्योग के नाम से भी जाना जाता हैं। आज भी लाखों लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध करा रहा है। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से है जहां कलात्मक, धार्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर दर्शनीय स्थलों एवं कृतियों की कमी नहीं है।

जीवन की रक्षा के लिए भी विकास के समांतर धरती को बचाने का संकल्प लेना होगा

सभ्यता की शुरूआत से ही प्रकृति और मनुष्य के बीच बहुत गहरा संबंध रहा है। दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं, लेकिन आज ऐसा लगता है कि इंसान को प्रकृति की उतनी रह गई है। इसमें दोराय नहीं कि पर्यावरण परवाह नहीं रह सिमटता नजर आ पर संतुलन को बनाए रखना आवश्यक है, लेकिन विकास इंसानी सभ्यता का एक जरूरी पहलू है। पहले जहां जंगल थे, चारों तरफ हरियाली थी, वहां अब सब कुछ है। बढ़ती आबादी के समांतर विकास एक अपरिहार्य स्थिति है। मगर इस क्रम में अनेक जगहों पेड़ों की अनियंत्रित कटाई के साथ ही जंगलों की स्थिति ऐसी कर दी गई है, आज । पारिस्थितिकी के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो रहा में पिछले कुछ वर्षों से जंगल लगातार कम होते जा रहे हैं। ऐसे दौर में, जब पर्यावरण विशेषज्ञ दुनियाभर में घटते जंगलों पर चिंता जता रहे हों, पर चिंता जता रहे हों, भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआइ) की रपट ने थोड़ी राहत दी है। जिसमे भारत इसके मुताबिक, वर्ष 2021 से 2023 तक भारत का कुल वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र 1,445 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। देश को हरा-भरा रखने में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और ओड़ीशा में भी दो साल पहले के मुकाबले हरियाली बढ़ी है। इससे संकेत मिलते हैं कि देश में कई वर्षों से जारी सामाजिक वन उत्सव और वृक्षारोपण ह्लऔर वक्षारोपण जैसी योजनाओं का असर दिखने लगा है। है। हालांकि रपट में ये तथ्य चिंताजनक है कि उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के राज्यों में वन एवं वृक्ष आवरण क्षेत्र घटा है।

पहली नजर में यह तथ्य राहत दे सकता है कि देश में में पिछले दो वर्षों में वन और वृक्ष क्षेत्र का दायरा देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के एक चौथाई से ज्यादा (25.17 फीसद) हो गया है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर यह दायरा की दृष्टि से लक्ष्य फिलहाल काफी बढ़ने के बावजूद पारिस्थितिकी सनक पारिस्थितिकीय स्थिरता कायम है। राष्ट्रीय वन नीति- 1988 के रखने के लिए देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कम से कम एक तिहाई हिस्सा वन क्षेत्र होना चाहिए। एफएसआइ ने सर्वेक्षण रपट की रपट की शुरूआत वर्ष 1987 में की थी। तब से अब तक दो फीसद ही बढ़ी हिस्सेदारी करीब है। जाहिर है, दुनिया के दूसरे देशों की की तरह जनसंख्या ॥ वृद्धि, शहरीकरण और औद्योगीकरण के कारण भारत में भी जंगल प्राकृतिक तौर पर फल- फल नहीं पा रहे हैं। विकास परियोजनाओं की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, , लेकिन खनन लिए जंगलों की कटाई बड़ी कटाई बड़ी समस्या है, पर सुप्रीम कोर्ट ने ने भी समय-समय पर चिंता जताई है।

गौरतलब है कि हरियाली क्षेत्र में जो बढ़ोतरी दर्ज की गई है, उसका अधिकतर हिस्सा प्राकृतिक वन क्षेत्र से बाहर है, जो वृक्षारोपण और कृषि आधारित वानिकी का नतीजा है। निश्चित रूप से इन प्रयासों का अपना महत्त्व है, लेकिन प्राका प्राकृतिक वन क्षेत्र के भरे-पूरे पेड़ों की तुलना शहरों में पौधरोपण अभियान से तब तक नहीं हो सकती, जब तक कि लगाए गए पौधे पूरी तरह विकसित नहीं हो जाते। ऐसे में वन संशोधन अधिनियम (2023) को लेकर चल रही बहस की अहमियत भी बढ़ जाती है। इस संशोधन में गैर वगीर्कृत जंगल का संरक्षण हटाने की बात है। गौर करने की बात है कि इस श्रेणी में कुल वनक्षेत्र का सोलह फीसद से ज्यादा हिस्सा आ जाता है, जो बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से संभावित से खतरे के दायरे में आ जाएगा। कहा जा सकता है, वृक्षारोपण और कृषि वानिकी के जरिए हरित क्षेत्र का दायरा बढ़ाने का प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय है, लेकिन प्राकृतिक वन क्षेत्र का संरक्षण भी उतना ही अहम है।

दुनिया तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ रही है, लेकिन हकीकत यह है कि शहरीकरण हमारी प्रकृति के सामने कहीं ज्यादा चुनौती पेश कर रहा है।

शहरों के विकसित होने के साथ-साथ दुनियाभर में हरियाली का दायरा सिकुड़ रहा है और कंक्रीट के जंगल बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, बिगड़ते पर्यावरणीय संतुलन और मौसम चक्र में आते बदलाव के कारण पेड़-पौधों की प्रजातियों के अलावा जीव-जंतुओं की कई प्रजातियों के अस्तित्व पर भी अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जबकि पर्यावरण का संबंध मानवीय जीवन में महत्त्वपूर्ण है।

यों कहें कि दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। विकास अनिवार्य है, लेकिन आज विकास के आगे पर्यावरण को हाशिये पर छोड़ दिया गया है। को भविष्य की कोई चिंता ही नहीं है। आज बढ़ती भर में वनों की कटाई हो ऐसा लगता है कि मनुष्य आबादी की जरूरतों को पूरा करने के करने के लिए दुनिया भर में रही है। बिगड़ते पर्यावरण से देश की जड़ी- -बूटियां लुप्त होने के कगार पर हैं। फसलों और फलों के उत्पादन पर भी इसका प्रभाव पड़ने लगा है।

भारत के भविष्य के लिए 21वीं सदी का कौशल महत्वपूर्ण क्यों है

विजय गर्ग

भारत के युवा, एक अनिश्चित समय में खड़े हैं। डिग्री के साथ सशस्त्र लेकिन 21वीं सदी में आवश्यक कौशल की कमी, वे कम वेतन वाली नौकरियों में फंस जाएंगे। जब तक शिक्षा सुधार, डिजिटल पहुंच और कौशल निर्माण की पहल को तत्काल पैमाने पर नहीं बढ़ाया जाता, तब तक जनसांख्यिकीय लाभांश का वादा खो जाएगा

भारत में युवाओं का दुनिया का सबसे बड़ा पूल है, लेकिन सही कौशल के बिना यह जनसांख्यिकीय लाभ एक जनसंख्यागत आपदा बन सकता है।

कार्य करने में विफलता कोई विकल्प नहीं है। निष्क्रियता के परिणाम भयानक होंगेः लाखों शिक्षित लेकिन कम कुशल युवा निम्न वेतन वाली नौकरियों में फंसे रहेंगे, जिससे निराशा और असमानता बढ़ जाएगी। हाल ही में, हमने नेपाल के साथ-साथ श्रीलंका और बांग्लादेश में भी अशांति देखी है, जहां बेरोजगार युवा राजनीतिक अभिजात वर्गों पर अपना क्रोध फैलाते हैं। भारत को इन चेतावनी संकेतों पर ध्यान देना चाहिए।

रोजगार संबंधी समस्या

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 15 सितंबर को जारी नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के आंकड़ों के अनुसार, युवा महिलाओं में बेरोजगारी काफी बढ़ गई है। 15-29 वर्ष की आयु वाली शहरी महिलाओं के लिए बेरोजगारी दर 25.7 प्रतिशत तक बढ़ गई है, जो कि युवा शहरी पुरुषों की तुलना में 10 प्रतिशत से अधिक है।

भारत कौशल रिपोर्ट 2025 एक कठोर वास्तविकता प्रस्तुत करती हैः इस वर्ष केवल 55 प्रतिशत भारतीय युवा रोजगार में हैं। रोजगार बाजार में प्रवेश करने वाले प्रत्येक दो युवा भारतीयों में से लगभग एक व्यक्ति अनुकूलन क्षमता, डिजिटल प्रवाह और लचीलापन की आवश्यकता वाली भूमिकाओं के लिए तैयार नहीं है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), अर्धचालक, स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण तथा हरित प्रौद्योगिकी जैसे उच्च मांग वाले क्षेत्रों में 29 मिलियन श्रमिकों की अनुमानित कमी से चेतावनी दी है। यह असंगति तकनीकी कौशल से परे है। विश्व बैंक ने पाया है कि नियोक्ता समस्या समाधान, सहयोग और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को उतना ही महत्व देते हैं जितना वे कोडिंग या इंजीनियरिंग करते हैं। इन ह्लमानव कौशलह्व वाले उम्मीदवार न केवल अधिक आसानी से नौकरी पाते हैं, बल्कि उच्च वेतन भी प्राप्त करते हैं।

नवाचार अंतर

21वीं सदी के कौशल की कमी से भारत में ह्लविचारशीलता का अंतरह्व भी बढ़ जाता है विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद, भारत अपनी सकल घरेलू उत्पाद का 0.7 प्रतिशत से भी कम अनुसंधान और विकास में निवेश करता है, जबकि चीन में 2.4 प्रतिशत और अमेरिका में 3 प्रतिशत से अधिक।

नतीजतन, जबकि चीन ने 2023 में लगभग 800,000 पेटेंट दायर किए थे, भारत मुश्किल से 30,000 दाखिल करने में कामयाब रहा।

यह असमानता भारतीय युवाओं में रचनात्मकता की कमी के कारण नहीं है; बल्कि शिक्षा प्रणाली से आती है, जो शायद ही कभी रचनात्मक सोच को बढ़ावा देती है। मूल सीखने और उच्च जोखिम वाली परीक्षाएं जिज्ञासा, डिजाइन

सोच या समस्या समाधान के लिए बहुत कम जगह छोड़ देती हैं। जब तक भारत अपनी शिक्षा प्रणाली में इन कौशल को शामिल नहीं करता, तब तक वह निमार्ता के बजाय वैश्विक नवाचारों का उपभोक्ता बने रहने का जोखिम उठाता है।

21वीं सदी के कौशल क्यों महत्वपूर्ण हैं

कार्यस्थल में तेजी से परिवर्तन हो रहा है, जो पारंपरिक पाठ्यपुस्तकों को बहुत पीछे छोड़ देता है। जैसे-जैसे सचिवालय की भूमिकाएं घटती जा रही हैं, नवीकरणीय ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, फिनटेक और जैव प्रौद्योगिकी में नौकरियां प्रमुख शक्तियों के रूप में सामने आती हैं। भविष्य की नौकरियों की रिपोर्ट 2025 स्पष्ट करती हैः 2030 तक आज के लगभग 40 प्रतिशत कौशल अप्रचलित हो जाएंगे।

21वीं सदी के कौशल केवल रोजगार की क्षमता से परे हैं; वे गरिमा, आत्मविश्वास और गतिशीलता का प्रतीक हैं। शोध इस बात को सुदृढ़ करता है, जिससे पता चलता है कि मजबूत सामाजिक-भावनात्मक कौशल वाले छात्र अकादमिक रूप से उत्कृष्ट हैं, अधिक कल्याण का आनंद लेते हैं और तनाव के प्रति कम संवेदनशील होते हैं।

हालांकि, इन परिणामों को प्राप्त करने के लिए प्रणालीगत परिवर्तन की आवश्यकता होती है। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की खाई बनी हुई हैः वर्तमान में केवल 57 प्रतिशत स्कूलों के पास कंप्यूटर तक पहुंच है, जबकि 54 प्रतिशत ही इंटरनेट से जुड़े हैं। ग्रामीण स्कूलों को असमान रूप से प्रभावित किया जाता है; कई गांवों में, बच्चे परीक्षा केंद्रों पर पहली बार लैपटॉप का सामना करते हैं। इसके अतिरिक्त, शिक्षकों की तैयारी और प्रशिक्षण दुखद रूप से अपर्याप्त है।

कई शिक्षकों को रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच विकसित करने के लिए आवश्यक डिजिटल साक्षरता और शैक्षणिक उपकरण की कमी होती है। श्लोक पूरा करने की आवश्यकता से अभिभूत, वे अक्सर मौलिक शिक्षण का सहारा लेते हैं।

सामाजिक असमानताएं लिंग, भूगोल और विकलांगताओं को प्रभावित करती हैं। केवल 36 प्रतिशत ग्रामीण किशोर लड़कियों के पास स्मार्टफोन है, जिससे डिजिटल सीखने की संभावनाओं तक उनकी पहुंच गंभीर रूप से सीमित हो जाती है। आदिवासी छात्र और विकलांग बच्चों को अक्सर उपलब्ध सामग्री की कमी का सामना करना पड़ता है।

इसके अलावा, अप्रचलित मूल्यांकन प्रणालियों ने नवाचार पर स्मृति को प्राथमिकता दी है। जब तक ये मूल्यांकन विकसित नहीं होते, तब तक स्कूलों में समस्या-समाधान या सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बहुत कम प्रोत्साहन होगा।

इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें पांच महत्वपूर्ण मोर्चों पर निर्णायक कार्रवाई करनी होगी

पाठ्यक्रम सुधारः 21वीं सदी के कौशल को मौलिक झ आवश्यक, वैकल्पिक या व्यावसायिक नहीं माना जाना चाहिए। उन्हें अलग-अलग मॉड्यूल के रूप में संलग्न करने की बजाय सभी विषयों पर एकीकृत किया जाना चाहिए।

शिक्षक सशक्तीकरणः हमें प्रशिक्षण ढांचे में संशोधन करना होगा, निरंतर व्यावसायिक विकास प्रदान करना होगा और शिक्षकों को सफल होने के लिए आवश्यक डिजिटल और सामाजिक-भावनात्मक शिक्षण उपकरण उपलब्ध कराएंगे।

इक्विटी एंड एक्सेसः डिजिटल अंतर को दूर करना आवश्यक है। हमें कम लागत वाली नवाचारों जैसे कि ऑफलाइन सामग्री, सहकर्मी क्लब और बहुभाषी संसाधन लागू करने की आवश्यकता है।

मूल्यांकन नवाचारः परियोजना-आधारित मूल्यांकन, पोर्टफोलियो और डिजिटल बैज की ओर बढ़ना महत्वपूर्ण है जो रचनात्मकता, टीमवर्क और समस्या समाधान क्षमताओं को सटीक रूप से दशार्ते हैं।

साझेदारीः हमें पायलट कार्यक्रमों को बढ़ाने और राष्ट्रीय पहल में आवश्यक कौशल सेट शामिल करने के लिए सीएसआर फंड, एडटेक प्लेटफॉर्म और उद्योग सहयोग का लाभ उठाना होगा

एक राष्ट्रीय अनिवार्य

यह सिर्फ भारतीय युवाओं को रोजगार देने के बारे में नहीं है; यह मूलतः राष्ट्र निर्माण के बारे में है। एक मजबूत कौशल पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना घरेलू स्तर पर नौकरियां पैदा करने के लिए आवश्यक है और साथ ही हमारे युवाओं को रोजगार से जुड़े प्रवास की तैयारी भी करनी चाहिए, क्योंकि पश्चिमी देश कुशल श्रमिकों की सक्रिय तलाश में हैं। यह ह्लप्रतिभा का परिपत्र प्रवाहह्व निस्संदेह धन हस्तांतरण, अंतर-सांस्कृतिक अनुभव और वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से भारत को समृद्ध करेगा, जिससे हमारा जनसांख्यिकीय लाभांश रणनीतिक वैश्विक लाभ में बदल जाएगा।

. यदि भारत इस क्षण का लाभ उठाता है, तो हमारे युवा न केवल राष्ट्रीय विकास बल्कि वैश्विक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए दुनिया की सबसे गतिशील कार्यबल बन सकते हैं।

विकल्प स्पष्ट है, और आगे का रास्ता निर्विवाद है। अनिवार्य बात यह नहीं है कि भारत 21वीं सदी के कौशल में निवेश करने का खर्च उठा सकता है, बल्कि वह इसे कितनी जल्दी और प्रभावी ढंग से कर सकता है। कार्रवाई का समय अब है। यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि प्रत्येक छात्र को 21वीं सदी में पनपने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान किए जाएं।

क्या पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच संबंध आपसी जरूरतों पर आधारित हैं ?

अशोक भाटिया

सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुआ रक्षा समझौता क्या वर्ल्ड ऑर्डर में एक बड़े बदलाव का संकेत है? सवाल यह इस कारण है कि क्या पश्चिम एशिया में खासतौर से जो देश अमेरिका की गुड बुक्स में रहे हैं, उनका भरोसा उससे हट रहा है?सऊदी-पाकिस्तान समझौते के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है कतर पर किया गया इजरायल का हमला। कतर अमेरिका का पुराना सहयोगी है। यहां साल 2000 से अमेरिकी सैन्य अड्डा है। कतर की राजधानी दोहा के पास मौजूद अल उदैद एयरबेस पश्चिम एशिया में अमेरिकी सेंट्रल कमांड के एयर ऑपरेशंस का मुख्यालय है। यहां करीब 8,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। कतर को लगता था कि इस वजह से वह इजरायल समेत किसी भी देश के हमले से महफूज है।मगर जब दोहा में हमास के नेताओं को मारने के लिए इजरायल ने हमला बोला, तो उसका यह भरोसा टूट गया। सऊदी अरब को भी लगा कि वह भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इजरायल की मिसाइलें सऊदी के एयरस्पेस को पार करके ही दोहा पहुंच सकती थीं। अभी तक ये सारे देश (मुस्लिम देश) विश्व कूटनीति में अमेरिका के साथी ही माने जाते रहे हैं।इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने ट्रंप को दोहा पर हमले के बारे में पहले ही बता दिया था। दबाव में आकर ट्रंप को भी मानना पड़ा कि उन्हें इसकी जानकारी थी। इस खुलासे ने पश्चिमी एशिया के देशों में खलबली पैदा की। वैसे भी सबके दिमाग में कतर द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को करोड़ों डॉलर की कीमत वाला हवाई जहाज गिफ्ट करने की छवि तरोताजा थी।अमेरिका की मुश्किले कई है जैसे कतर में अमेरिकी सैन्य अड्डा, फिर भी इजरायल ने किया हमला वगैरह . बताया जाता है कि इसीलिए सऊदी-पाक में हुआ करार हुआ है .

वैसे भारत ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हाल के समझौते पर कोई टिप्पणी नहीं की। भारत ने यह कहकर सावधानी से जवाब दिया कि वह दोनों देशों के बीच

समझौते का अध्ययन कर रहा है। सऊदी अरब के साथ भारत के संबंध मजबूत हैं। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल सऊदी अरब का दौरा किया। भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय व्यापार 50 बिलियन डॉलर से अधिक है। सऊदी अरब अपने कच्चे तेल का 20 प्रतिशत से अधिक भारत को निर्यात करता है। अप्रैल 2025 में, दोनों ने रक्षा सहयोग पर हस्ताक्षर किए। एक समिति का गठन किया गया। इसमें संयुक्त अभ्यास शामिल हैं। अब जब सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ समझौता हो गया है और पाकिस्तान के नेता समझौते को लेकर जो कुछ भी कहें, सऊदी अरब भारत के साथ संतुलन बनाएगा। सऊदी अरब पाकिस्तान की लड़ाई नहीं लड़ेगा; लेकिन यह ईरान जैसे क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों से निपटने में मदद करेगा। यदि भारत और पाकिस्तान फिर से टकराते हैं, तो सऊदी अरब आर्थिक दबाव डाल सकता है; पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच यह समझौता कतर पर इजरायल के हमले के आठ दिन बाद हुआ है। पाकिस्तान और सऊदी अरब संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेंगे, भले ही समझौते को इजरायल को उकसाने के लिए चित्रित किया जा रहा है। समझौते के बाद भारत ने यह उम्मीद जताई है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच संबंध आपसी जरूरतों पर आधारित हैं। सऊदी अरब वित्तीय सहायता प्रदान करता है और पाकिस्तान सैन्य सहायता प्रदान करता है। पाकिस्तान सऊदी अरब के नेतृत्व में सैन्य प्रयासों में शामिल है।

पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख राहील शरीफ ने 2015 से इस्लामिक सैन्य आतंकवाद विरोधी गठबंधन का नेतृत्व किया है। माना जाता है कि 2018 में, पाकिस्तान ने यमन में चल रहे संघर्ष में मदद के लिए सऊदी अरब में सेना भेजी थी। वह बारह सौ से दो हजार पाकिस्तानी सैनिक पहले से ही सऊदी अरब में तैनात हैं। इसके बदले में पाकिस्तान को सऊदी अरब से आर्थिक मदद मिलती रहेगी। पाकिस्तान को उम्मीद है कि भविष्य में भारत के साथ किसी भी संघर्ष के मामले में सऊदी अरब कुछ मदद करेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच ह्यरणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौतेह्न का क्या मतलब है। भारत ने सऊदी सशस्त्र बलों को प्रशिक्षित करने की पेशकश की है। भारत और सऊदी अरब के बीच साझेदारी हाल के महीनों में बढ़ी है, जिसमें दोनों देशों और रक्षा मंत्रिस्तरीय समिति के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शामिल हैं। स्थापना में ये चरण शामिल हैं। यह उनके रिश्ते को मजबूत करने का प्रतीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष शुरू होने पर तटस्थ रहने का फायदा सऊदी अरब को मिला है।

जब इस साल मई में भारत और पाकिस्तान के बीच झड़प हुई थी, तो सऊदी अरब ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की थी। लेकिन ह्यऑपरेशन सिंदूरह्न पर कोई बयान जारी नहीं किया गया। भारत सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान से अधिक महत्वपूर्ण है और भारत के साथ उसकी आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है, यह बात पाकिस्तान के साथ रक्षा सौदे के बाद भी सऊदी के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दोहराई गई है। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि पाकिस्तान को सऊदी अरब से लगातार बड़े और किफायती ऋण मिल रहे हैं। कि मूल रूप से एक साल के लिए दिया गया कर्ज पाकिस्तान की ओर से नहीं चुकाया गया है। सऊदी सरकार पाकिस्तान के प्रति उदार रही है और हर साल बिना किसी अतिरिक्त ब्याज के इन ऋणों को देती रही है। सऊदी अरब का पाकिस्तान को दिया जाने वाला ऋण चीन की तुलना में एक तिहाई सस्ता है और विदेशी वाणिज्यिक ऋण की लागत का आधा है। सऊदी अरब, चीन और संयुक्त अरब अमीरात ने तीन साल के कार्यक्रम के पूरा होने तक पाकिस्तान को अपनी नकदी जमा रखने की शर्त रखी है। इन देशों ने पाकिस्तान को कुल 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर का उधार दिया है, जो पाकिस्तानी केंद्रीय बैंक के 14.3 बिलियन डॉलर के कुल विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा है। अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब एक साथ आ भी जाते हैं, तो भारत पर रक्षात्मक रूप से कोई असर नहीं पड़ेगा। ग्लोबल फायरपावर इंडेक्स के अनुसार, भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है, जबकि पाकिस्तान बारहवें स्थान पर है। सऊदी अरब 24वें स्थान पर है। सऊदी अरब की ताकत अमेरिकी हथियारों में निहित है। सऊदी अरब को 2015-2022 यमन युद्ध में हौथी विद्रोहियों द्वारा ड्रोन हमलों से भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसने इसकी हवाई सुरक्षा को कुछ हद तक कमजोर कर दिया। सऊदी सेना विदेशी (पाकिस्तानी और अमेरिकी) सलाहकारों पर निर्भर है और उनके पास आंतरिक प्रशिक्षण की कमी है। यह समझौता भारत के लिए दोधारी तलवार है। एक ओर, भारत और सऊदी अरब के बीच मजबूत आर्थिक संबंध हैं।

भारत सऊदी अरब के साथ सौ अरब डॉलर से ज्यादा का व्यापार करता है।

आर्थिक स्वतंत्रता का नया अध्याय

डॉ नीलम महेंद्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हालिया उद्घोष झ ह्लभारत का सबसे बड़ा दुश्मन कोई विदेशी ताकत नहीं, बल्कि हमारी निर्भरता है !ह्व

1947 में मिली आजादी, एक स्वर्ण किरण थी! हमने तिरंगा फहराया, राष्ट्रगान गाया और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में साँस ली। पर क्या वो स्वतंत्रता पूरी थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हालिया उद्घोष झ ह्लभारत का सबसे बड़ा दुश्मन कोई विदेशी ताकत नहीं, बल्कि हमारी निर्भरता है !ह्व झ इस गहन प्रश्न को एक बार फिर से जीवंत कर गया है। यह सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि हमारे सामूहिक विवेक को झकझोरने वाला सत्य है, जो हमें उस शीशे के सामने खड़ा कर देता है जहाँ हमारी राजनीतिक आजादी की चमक, आर्थिक और डिजिटल पराधीनता की धुंध में खोई हुई दिखती है।

कल्पना कीजिए एक विशाल वृक्ष की, जिसकी जड़ें तो अपनी मिट्टी में हैं, पर उसकी शाखाएँ और फल दूसरों के बगीचे में उग रहे हों। कुछ ऐसी ही स्थिति रही है हमारी। हमारे सैनिक, जो देश की सीमा पर सीना ताने खड़े हैं, उनके हथियार अक्सर विदेशी फैक्ट्रियों से आते रहे। हमारे युवाओं के सपनों को पंख देने वाले विश्वविद्यालय अक्सर सात समंदर पार पाए गए। और हमारी डिजिटल धड़कनें? वे अमेरिकी कंपनियों के अदृश्य एल्गोरिद्म के इशारों पर नाचती रहीं। यह कैसी आजादी है, जहाँ हम शरीर से स्वतंत्र हैं पर आत्मा से अभी भी बंधे हुए हैं?

क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी अर्थव्यवस्था की नसों में कौन-सा रक्त बह रहा है? ढ६उ, ऊीङ्घ३३ी, ए और ङढटॠ झ ये चार विशालकाय कंपनियाँ, जिन्हें हम ह्यबिग फोरह्न कहते हैं, दशकों से भारत की आर्थिक धमनियों पर अपना कब्जा जमाए बैठी हैं। ढ६उ ने तो 1880 में ही कोलकाता में अपने तंबू गाड़ दिए थे झ जब भारत में अंग्रेजों का राज था! ए 1914 से यहाँ है,सोशल मीडिया पर इन कंपनियों द्वारा भारत से लूटे जा रहे अरबों-खरबों रुपयों की बहस छिड़ी रहती है झ कोई 38,000 करोड़ कहता है, कोई 45,000 करोड़। पर असली खेल पैसों का नहीं, बल्कि ह्यडेटाह्न का है! ठरए में सूचीबद्ध कंपनियों ने पिछले साल लगभग 1,903 करोड़ ऑडिट फीस दी, जिसमें से बिग फोर का हिस्सा 550झ600 करोड़ था। यह रकम भले ही छोटी लगे, पर इसका महत्व ह्यकुबेर के खजानेह्न से कम नहीं।

ये फर्में जानती हैं कि कौन-सी भारतीय कंपनी कहाँ से कच्चा माल खरीदती है, किस भाव बेचती है, किस सेक्टर में हमारी ताकत है और कहाँ हमारी नसें कमजोर हैं। यह जानकारी सोने से भी ज्यादा कीमती है! यही वो खुफिया जानकारी है जिसका इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियाँ हमें जैसी रैंकिंग थमाने के लिए करती हैं। यानी, हमारा ही डेटा हमारे खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल होता है। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि यह सिर्फ व्यापार का मामला नहीं बल्कि यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का हृदय-भेदी प्रश्न है!

इस अदृश्य खतरे को चीन ने बहुत पहले पहचान लिया था। वहाँ विदेशी ऑडिट फर्मों पर ड्रैगन की कड़ी निगरानी रहती है। ढ६उ को तो चीन में उसकी रियल एस्टेट कम्पनी ल्लाी मामले में भारी आर्थिक दंड और छ माह का प्रतिबंध भी भुगतना पड़ा था।

रूस ने भी यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी सेवाओं को सीधे-सीधे रेड कार्ड दिखा दिया और श्ङ तथा जैसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खड़े कर लिए। ये देश दुनिया को चिल्ला-चिल्लाकर बता रहे हैं कि आत्मनिर्भरता केवल एक जोशीला नारा नहीं, बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता का अंतिम गढ़ है।

अब भारत भी उसी चौराहे पर खड़ा है, जहाँ उसे अपना रास्ता खुद बनाना है। मोदी सरकार का सपना है कि भारत अपनी खुद की ह्लग्रुप ऑफ फोरह्व फर्मों का निर्माण करे। ऐसी भारतीय कंपनियाँ, जो न केवल हमारे देश की कंपनियों का ऑडिट करें, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी अपनी विश्वसनीयता का लोहा मनवाएँ। हालांकि यह चुनौती आसान नहीं है क्योंकि कंपनियों ने सौ साल में अपना साम्राज्य खड़ा किया है, पर यह असंभव भी नहीं है!

जापान में 6 तीव्रता वाले भूकंप के तेज झटके

एजेंसी

टोक्यो। जापान में रात होन्शू के पूर्वी तट पर 6 तीव्रता के भूकंप से धरती कांप उठी। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (एनसीएस) के अनुसार, होन्शू के पूर्वी तट के पास 6.0 तीव्रता का भूकंप आया। इसका केंद्र जमीन से करीब

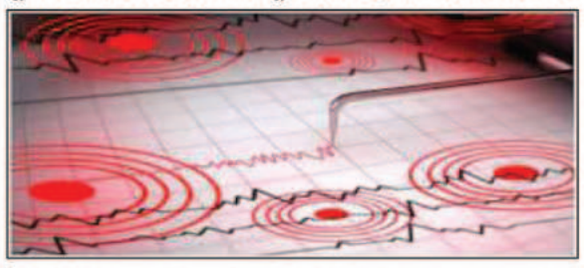

50 किलोमीटर गहराई में था। फिलहाल किसी बड़े नुकसान या सुनामी की चेतावनी नहीं है। उल्लेखनीय है कि जापान अत्यंत सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र में है। इसके द्वीपों में अक्सर भूकंप आते हैं। यहां कई विनाशकारी भूकंप आ चुके हैं, जो सुनामी का कारण बनते हैं।

फिलिस्तीनी एनजीओ ने मलबे में दबे हजारों शवों को निकालने के लिए अंतरराष्ट्रीय मदद की लगाई गुहार

गाजा। लगभग दो वर्षों से जारी युद्ध के बीच गाजा में अब भी हजारों फिलिस्तीनी नागरिक मलबे के नीचे दबे पड़े हैं। इस बीच, पैलेस्टीनियन सेंटर फॉर द मिसिंग एंड फोर्सिबली डिसअपियर्ड नामक एक स्थानीय गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से तत्काल सहायता की अपील की है, ताकि इन शवों को बाहर निकाला जा सके और उनकी पहचान की जा सके। एनजीओ ने चेतावनी दी है कि यदि तत्काल अंतरराष्ट्रीय मदद नहीं मिली तो करीब 9,000 लोगों के शव कभी भी बरामद नहीं हो पाएंगे। वहीं गाज़ा सिविल डिफेंस के अनुसार, अनुमानित 15,000 शव अब भी मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अप्रैल 2025 में जारी अनुमान के मुताबिक, अक्तूबर 2023 से अब तक गाजा की 92 प्रतिशत आवासीय इमारतें यानी लगभग 4.36 लाख घर पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। भारी तबाही के कारण बड़ी संख्या में लोग ध्वस्त इमारतों के नीचे फंस गए। गाजा में राहत और बचाव उपकरणों की भारी कमी है और सीमित संसाधनों के चलते स्थानीय टीमें सभी प्रभावित इलाकों तक नहीं पहुंच पा रहीं। एनजीओ ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से फॉरेंसिक विशेषज्ञों, खुदाई मशीनों और मोबाइल डीएनए प्रयोगशालाओं को तुरंत भेजने की अपील की है, ताकि शवों को निकाला और पहचाना जा सके। संगठन ने कहा कि इन संसाधनों के बिना, हजारों परिवार अपने प्रियजनों को सम्मानजनक अंतिम संस्कार देने से वंचित रह जाएंगे।

ट्रंप ने गाजा संघर्षविराम योजना के त्वरित कार्यान्वयन की मांग की, कहा- 'देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी'

एजेंसी

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इजराइल ने अस्थायी रूप से गाजा में अपने बमबारी अभियान को रोक दिया है, जिसे उन्होंने शांति समझौते को अंतिम रूप देने और हमास के कब्जे में बंधकों की रिहाई की दिशा में एक अहम कदम बताया। ट्रंप ने चेतावनी दी कि हमास को अब तेजी से कदम उठाने होंगे, अन्यथा सभी शर्तें समाप्त हो जाएंगी। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर लिखा, मैं किसी भी देरी को बर्दाश्त नहीं करूंगा, जिसकी कई लोगों को आशंका है, और न ही ऐसा परिणाम स्वीकार करूंगा जिसमें गाजा फिर खतरा बने। चलिए, इसे तेजी से पूरा करें। सभी के साथ न्याय होगा! उन्होंने इजराइल की ओर से बमबारी रोकने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि यह बंधकों की रिहाई और शांति समझौते को पूरा करने का अवसर देता है। हालांकि, सीएनएन की एक रिपोर्ट के अनुसार, गाजा में अब तक कम से कम 67 लोगों की मौत इजराइली हमलों में हुई है, जिसकी पुष्टि स्थानीय अस्पताल अधिकारियों ने की है। एक दिन पहले, ट्रंप ने खुलासा किया था कि हमास ने उनके 20-सूत्रीय शांति प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने अपने वीडियो संदेश में इसे एक बड़ा दिन बताते हुए कहा था कि यह ऐतिहासिक घटनाक्रम है। ट्रंप प्रशासन की मध्यस्थता में तैयार यह प्रस्ताव गाजा में लगभग दो साल से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

वेनेजुएला के पास एक नाव पर अमेरिकी हवाई हमले में 4 की मौत

वाशिंगटन। अमेरिका ने वेनेजुएला के तट से कुछ दूर अवैध मादक पदार्थ ले जा रही एक नाव पर हवाई हमला किया जिसमें चार लोगों के मारे जाने की खबर है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने एक्स पर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हाल के हफ्तों में वेनेजुएला के आसपास के क्षेत्रों में अमेरिका का यह चौथा हमला है। हेगसेथ ने कहा कि यह हमला अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा में किया गया और इसमें मारे गए सभी लोग पुरुष थे। उन्होंने कहा कि ये हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक अमेरिकी लोगों पर हमले समाप्त न हो जाएं। हेगसेथ द्वारा साझा लगभग 40 सेकंड के एक वीडियो में हमले की फुटेज है। हालांकि नाव में मादक पदार्थ होने का कोई सबूत दिए बिना उन्होंने कहा कि खुफिया जानकारी पुष्टि करती है कि नाव पर मादक पदार्थ थे और उसपर मौजूद लोग नार्को-आतंकवादी थे। उन्होंने मादक पदार्थ की मात्रा या प्रकार का खुलासा नहीं किया। इस बीच वेनेजुएला के संचार मंत्रालय ने इस बाबत अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है।

पीटर मुथारिका ने दूसरी बार संभाली मलावी की सत्ता, भ्रष्टाचार खत्म करने और अर्थव्यवस्था सुधारने का वादा

एजेंसी

ब्लैंटायर (मलावी)। मलावी के पीटर मुथारिका ने देश के राष्ट्रपति पद की शपथ लेकर अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत की। 85 वर्षीय मुथारिका ने पिछले महीने हुए चुनावों में 56 प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त कर 70 वर्षीय निवर्तमान राष्ट्रपति लाजरस चकवेरे को पराजित किया, जिन्हें आर्थिक संकट से जूझ रहे देश की जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया। यह मुथारिका और चकवेरे के बीच चौथा राष्ट्रपति मुकाबला था।

शपथ ग्रहण समारोह वाणिज्यिक शहर ब्लैंटायर के एक स्टेडियम में हुआ, जहां डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के नीले और सफेद रंग में सजे समर्थकों, सरकारी अधिकारियों और अफ्रीकी देशों के राष्ट्राध्यक्षों की भीड़ उमड़ी थी। अपने उद्घाटन भाषण में मुथारिका ने कहा कि उनकी सरकार को एक गंभीर आर्थिक संकट झेल रहे देश की बागडोर मिली है। उन्होंने बताया कि देश खाद्य संकट,

जीवनयापन की बढ़ती लागत और विदेशी मुद्रा की कमी से जूझ रहा है, जिससे व्यवसाय ठप हो गए हैं और ईंधन संकट बना हुआ है। मुथारिका ने कहा कि सरकार के पास पैसा नहीं है। कर्ज का बोझ बहुत बढ़ गया है और किसी को नहीं पता कि उधार लिया गया धन कहां गया। उन्होंने दृढ़ता के साथ कहा, ÷हम इस देश को सुधारेंगे। मैं दूध और शहद का वादा नहीं करता, बल्कि कड़ी मेहनत और कठिन फैसलों का वादा करता हूं। सरकारी लूट का दौर अब खत्म होगा। राष्ट्रपति ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से निवेश का आह्वान किया और विशेष रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संबोधित करते हुए कहा कि वे शीघ्र ही अमेरिका में एक प्रतिनिधिमंडल भेजेंगे ताकि अमेरिकी सहायता में कटौती के बाद मलावी की आर्थिक संभावनाओं पर चर्चा की जा सके। इस बीच, चकवेरे की मलावी कांग्रेस पार्टी ने एक बयान जारी कर कहा कि यद्यपि निवर्तमान राष्ट्रपति शपथ समारोह में उपस्थित नहीं थे, उन्होंने मुथारिका को सफलता और अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दी हैं।

काठमांडू के मौसम में सुधार के साथ ही नेपाल से घरेलू उड़ानें शुरू

एजेंसी

काठमांडू। दो दिनों की लगातार बारिश के कारण निलंबित घरेलू उड़ानें रविवार सुबह से त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से फिर से शुरू हो गई हैं। हवाई अड्डा प्रशासन के अनुसार उन मार्गों पर उड़ानें फिर से शुरू हो गई हैं, जहां मौसम की स्थिति में सुधार हुआ है। आज सुबह काठमांडू से नेपालगंज और भद्रपुर के लिए उड़ानें पहले ही शुरू हो चुकी हैं। यह भी पुष्टि की गई कि पोखरा और सुरखेत में मौसम की स्थिति अब हवाई यात्रा के लिए अनुकूल हो गई है, जिससे उन मार्गों पर भी संचालन फिर से शुरू हो गया है। इस बीच, आज सुबह से ही अंतरराष्ट्रीय उड़ानें नियमित रूप से शुरू की जा चुकी हैं। शुक्रवार शाम से ही आंतरिक उड़ाने बाधित हो गई थी। भारी बारिश के कारण अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भी बाधित रही। अधिकतर अंतराष्ट्रीय उड़ानों को भारत के नई दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी और कोलकाता डाइवर्ट किया गया था।

नेपाल में भूस्खलन और बाढ़ से तबाही, 36 घंटे में 40 लोगों की मौत

एजेंसी

काठमांडू। पिछले दो दिनों के भीतर देश भर में विभिन्न आपदाओं के दौरान 40 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 13 अन्य बाढ़, भूस्खलन, बिजली गिरने और सड़क दुर्घटनाओं के कारण घायल हो गए हैं।

सशस्त्र पुलिस बल (एपीएफ) के प्रवक्ता शैलेंद्र थापा ने बताया कि अकेले इलाम जिले में बाढ़ और भूस्खलन से 28 लोगों की मौत हो गई है और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इसके अतिरिक्त आपदा से संबंधित घटनाओं में 11 लोगों के लापता होने की सूचना है। इलाम जिले के सूर्योदय नगरपालिका में पांच, इलाम नगरपालिका में छह, देवमाई नगरपालिका में दो, फाक्फोक्थुम ग्रामीण पालिका में एक, मंगसेबुंग ग्रामीण नगर पालिका में तीन, मैजोगमाई ग्रामीण पालिका में आठ और संदकपुर ग्रामीण पालिका में तीन मौतें हुई हैं। प्रवक्ता थापा के

मुताबिक उदयपुर जिले में दो, रौतहट जिले में तीन, रसुवा में चार और काठमांडू में एक मौत हुई है। अलग-अलग घटनाओं में खोटांग, भोजपुर, रौतहट और मकवानपुर जिलों में बिजली गिरने से आठ लोग घायल हो गए। इस बीच, पांचथर जिले में एक और भूस्खलन के कारण सड़क दुर्घटना में छह लोगों की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए।

रूसी ड्रोन हमले में यूक्रेनी रेलवे स्टेशन पर तबाही, दर्जनों घायल

एजेंसी

कीव (यूक्रेन)। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बताया कि रूस ने देश के उत्तरपूर्वी शहर शोस्तका के रेलवे स्टेशन पर 'क्रूर' ड्रोन हमला किया, जिसमें कम से कम 30 लोग घायल हो गए। यह शहर कीव से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर, रूसी सीमा के निकट स्थित है। जेलेंस्की ने कहा, सभी आपात सेवाएं मौके पर पहुंच चुकी हैं और घायलों को सहायता दी जा रही है। सभी घायलों की जानकारी जुटाई जा रही है। यूक्रेन की राष्ट्रीय रेल सेवा उक्रजालिजनित्सिया के प्रमुख ओलेक्जांद्र पर्टसोव्स्की ने इसे 'हमारे सीमावर्ती समुदायों से संपर्क तोड़ने की नीच कोशिश' बताया।

यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री ओलेक्सी कुलेबा ने बताया कि रूस ने दो यात्री ट्रेनों को निशाना बनाया, पहले एक स्थानीय ट्रेन और फिर कीव जा रही दूसरी ट्रेन पर हमला किया गया। उन्होंने कहा कि दूसरा ड्रोन उस समय गिरा जब लोग पहले हमले के बाद निकासी अभियान में जुटे थे। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय के शीर्ष राजनयिक अंद्री सिबिहा ने इसे रूस की 'डबल स्ट्राइक' रणनीति बताया, जिसमें बचावकर्मियों और निकासी कर रहे नागरिकों को दोबारा निशाना बनाया जाता है। हमले से शोस्तका और आसपास के क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई। राष्ट्रपति जेलेंस्की और स्थानीय गवर्नर ओलेह ह्विगोरोव ने घटनास्थल की तस्वीरें साझा कीं, जिनमें एक यात्री कोच आग की लपटों में घिरा दिखाई दे रहा है।

रूस में ईंधन संकट, यूक्रेन का पलटवार

इसी बीच, यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी सेना ने रूस के किरिशी रिफाइनरी (सेंट पीटर्सबर्ग के पास) पर ड्रोन हमला किया है। यह रिफाइनरी रूस की सबसे बड़ी

इकाइयों में से एक है और प्रतिदिन लगभग 3.55 लाख बैरल कच्चा तेल प्रोसेस करती है। रूसी अधिकारियों ने बताया कि सात ड्रोन गिरा दिए गए और औद्योगिक क्षेत्र में लगी आग पर काबू पा लिया गया। लगातार यूक्रेनी हमलों और घरेलू मांग बढ़ने के कारण रूस को हाल के महीनों में पेट्रोल की कमी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि रूस अब भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश बना हुआ है।

नेतन्याहू बोले- अगले कुछ दिनों में सभी बंधकों की वापसी की उम्मीद, इजराइल एक बड़ी उपलब्धि के कगार पर

एजेंसी

यरूशलेम। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जारी एक वीडियो संदेश में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में सभी बंधक (जीवित और मृत दोनों) वापस लौट आएंगे। उन्होंने कहा कि इजराइल ÷एक बहुत बड़ी उपलब्धि के कगार पर÷ है, हालांकि समझौता अभी अंतिम नहीं हुआ है और इस दिशा में कड़ी मेहनत जारी है।

नेटन्याहू ने कहा, ईश्वर की कृपा से आने वाले दिनों में, सुक्कोत त्योहार के दौरान, हम सभी बंधकों की वापसी की घोषणा कर सकेंगे, जबकि इजराइली सेना (आईडीएफ) अब भी गाजा में तैनात रहेगी। प्रधानमंत्री ने बताया कि अब तक 207 बंधकों की वापसी हो चुकी है, लेकिन मैंने कभी शेष बंधकों को लेकर उम्मीद नहीं छोड़ी, न ही युद्ध के लक्ष्यों को। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ समन्वय में की गई कूटनीतिक पहल ने स्थिति को पूरी तरह बदल दिया है। नेतन्याहू के अनुसार, अब इजराइल नहीं, बल्कि हमास अलग-थलग पड़ेगा। उन्होंने कहा कि

योजना के पहले चरण में सभी बंधकों को रिहा किया जाएगा और आईडीएफ गाजा में ऐसे स्थानों पर पुनः तैनात होगी, जिससे वह इलाके की निगरानी जारी रख सके। नेतन्याहू ने स्पष्ट किया कि हमास को रिहाई पर सहमत कराने में सिर्फ सैन्य और कूटनीतिक दबाव ने भूमिका निभाई है। उन्होंने आलोचकों के उस दावे को खारिज किया कि ÷हमास एक या दो साल पहले बिना आईडीएफ की वापसी के भी सभी बंधकों को छोड़ने को तैयार था। नेतन्याहू ने कहा, यह पूरी तरह झूठ है। हमास का रुख सिर्फ हमारे दबाव की वजह से बदला। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय और घरेलू भारी दबाव के बावजूद युद्ध जारी रखने के अपने फैसले को सही ठहराया और राष्ट्रपति ट्रंप का ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कड़े रुख और समर्थन के लिए धन्यवाद किया। नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने इजराइल की वार्ता टीम, जिसकी अगुवाई रणनीतिक मामलों के मंत्री रॉन डर्मर कर रहे हैं, को काहिरा रवाना होने का निर्देश दिया है ताकि बंधक रिहाई से जुड़ी तकनीकी औपचारिकताएं पूरी की जा सकें। उन्होंने कहा, हमारा और हमारे अमेरिकी मित्रों का इरादा है कि वार्ता कुछ ही दिनों में पूरी हो जाए,÷ साथ ही जोड़ा कि ट्रंप ने आज स्पष्ट कर दिया है कि वे हमास की किसी भी देरी की रणनीति को बर्दाश्त नहीं करेंगे। नेतन्याहू ने बताया कि समझौते के दूसरे चरण में हमास को निशस्त्र किया जाएगा और गाजा पट्टी को पूर्णतः सैन्यीकरण-मुक्त बनाया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी,यह या तो ट्रंप योजना के तहत कूटनीतिक तरीके से होगा, या फिर हमारे सैन्य बल के जरिए।

कोशी बैराज पर यातायात रोका गया, बिहार में भी बाढ़ का खतरा बढ़ा

एजेंसी

काठमांडू। कोशी बैराज के पुल पर यातायात और पैदल चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। बैराज प्रशासन के ई. मनोज कुमार के मुताबिक कोशी नदी का पानी पुल की सड़क तक पहुंच गया है, जिसके बाद नेपाल और भारत के अधिकारियों की संयुक्त बैठक में यातायात रोकने का फैसला लिया गया है। लगातार तीसरे दिन हो रही बारिश के कारण कोशी नदी का जलस्तर एक्सट्रीम डेंजर लेवल के पार कर गया है। ई. मनोज कुमार ने बताया कि बराज के सभी 56 फाटक खोल दिए गए हैं। ताजा अपडेट के मुताबिक इस समय कोशी बैराज से 4 लाख 86 हजार क्यूसेक पानी प्रति सेकेंड के हिसाब से छोड़ा जा रहा है। इस कारण नेपाल के दक्षिणी तटीय इलाकों के साथ ही बिहार में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।

ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर नाम और आकृति उकेरने का मोह पर्यटक जोड़े को महंगा पड़ गया

एजेंसी

बीजिंग। पर्यटक स्थलों या सार्वजनिक जगहों पर अपना या अपने मित्र का नाम अथवा खास किस्म की आकृति उकेरने की प्रवृत्ति अक्सर देखी जाती है।भारत सहित दूसरे देशों के लोग भी इस प्रवृत्ति के मारे हैं। हालांकि चीन में ऐसी हरकत करने वाले एक पर्यटक जोड़े को ऐसा करना महंगा पड़ गया।इस जोड़े ने यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल चीन की दीवार पर अपने-अपने नाम और खास किस्म की आकृति उकेरी।जांच में शिकायत सही पाए जाने पर इस जोड़े को न केवल हिरासत में लिया गया बल्कि उनपर भारी भरकम जुर्माना भी ठोका गया। ग्लोबल टाइम्स की एक खबर के मुताबिक बीजिंग नगर निगम लोक सुरक्षा ब्यूरो की मियोन शाखा ने रविवार को अधिसूचना जारी कर बताया कि चीन की दीवार की ईंटों पर अक्षर उकेरने वाले दो पर्यटकों को

हिरासत में लिया गया है और उन पर जुर्माना लगाया गया है। बीजिंग के एक कर्मचारी ने शुक्रवार को पुलिस से इसकी शिकायत की जिसमें बताया गया था कि पर्यटकों ने महान दीवार के सिमाताई खंड पर भ्रमण के दौरान अक्षर उकेरे थे। पुलिस ने मौके का निरीक्षण और विस्तृत जाँच कर पर्यटकों मान (पुरुष, 26) और लियू (महिला, 21) को गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि दोनों पर्यटकों ने शुक्रवार दोपहर 2:00 बजे दर्शनीय क्षेत्र में अपनी यात्रा शुरू की और शाम लगभग 4:30 बजे, मान ने लियू के सुझाव पर पत्थरों का उपयोग करके महान दीवार के एक टॉवर पर उनके नाम उकेरे और कुछ आकृतियाँ भी बनाईं। मियोन पुलिस ने मान और लियू पर नजरबंदी और जुर्माना सहित प्रशासनिक दंड लगाया है। पुलिस ने पर्यटकों को सांस्कृतिक अवशेषों की सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन करने, सभ्य पर्यटक का तौर तरीका अपनाने और महान दीवार की यात्रा के दौरान अपशेषों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ से बचने को कहा है। उल्लेखनीय है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से विख्यात चीन की दीवार, उत्तरी चीन में स्थित है। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए इसका निर्माण किया गया था।

नेपाल की आठ प्रमुख नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, कई जिलों में बाढ़ का खतरा

एजेंसी

काठमांडू। लगातार बारिश ने नेपाल की आठ प्रमुख नदियों को खतरे के स्तर से ऊपर धकेल दिया है। बागमती, कोशी, अरुण, तामोर, कोशी, बुधिखोला (सुनसरी) और बीरिंग खोला (झापा) नदियों में जल स्तर खतरे की सीमा को पार कर गया है। बाढ़ पूर्वानुमान प्रभाग के प्रमुख बिनोद पराजुली ने कहा कि अतिरिक्त 12 नदी स्टेशनों ने अलर्ट मार्क से ऊपर जल स्तर की सूचना दी है। उन्होंने कहा कि कोशी प्रांत में नदी का स्तर अभी भी बढ़ रहा है, जबकि बागमती और मधेश प्रांत के कुछ हिस्सों में या तो स्थिर है या धीरे-धीरे कम हो रहा है। विभाग ने यह भी बताया कि कोशी, माधेश और बागमती प्रांतों में अधिकांश नदियां और धाराएं अलर्ट स्तर के करीब हैं। बागमती और मधेश प्रांतों में बारिश कम होने लगी है,

लेकिन कोशी प्रांत के कई क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश जारी है। आज सुबह जारी एक बुलेटिन में विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ घंटों तक वर्तमान मौसम का पैटर्न बने रहने की संभावना है। आज शाम तक प्रभावित नदियों में उच्च बाढ़ के जोखिम का अनुमान लगाया गया है, जिसमें सोमवार सुबह तक मध्यम जोखिम जारी रहने की उम्मीद है।

फिलिस्तानी के समर्थन में पुर्तगाल में प्रदर्शन

लिस्बन। पुर्तगाल के लिस्बन शहर में 3,000 से ज़्यादा लोग फ़िलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने और गाज़ा में मानवीय सहायता पहुँचाने की कोशिश करने पर इज़रायल द्वारा हिरासत में लिए गए तीन पुर्तगाली नागरिकों की रिहाई की माँग को लेकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने कहा कि रैली के दौरान आयोजकों की उम्मीदों से कहीं ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए। लगभग 500 लोगों के आने की उम्मीद थी, लेकिन अंततः भीड़ लगभग 3,000 तक पहुँच गयी। रैली में भाग लेने वालों में पूर्व वामपंथी ब्लॉक नेता फ़्रांसिस्को लौका और कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार एंटोनियो फ़िलिप भी शामिल थे। समाचार एजेंसी से बात करते हुए श्री लौका ने कहा कि फ़िलिस्तीनी मुद्दों के लिए आंदोलन 'दुनिया भर में व्यापक पैमाने पर' हो रहा है। उन्होंने कहा, इज़रायली सरकार के ख़िलाफ़ इस आंदोलन को रोकना असंभव है, जैसा कि पूरे यूरोप में हो रहे प्रदर्शनों में देखा जा रहा है। फ़िलिस्तीन के सामाजिक कार्यकर्ता सेरेना सबात ने संबोधित किया और फ़िलिस्तीनी नागरिकों के ख़िलाफ़ चल रही कार्रवाइयों की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से ऐसी स्थितियों को जारी न रहने देने का आग्रह किया। इज़रायल द्वारा हिरासत में लिए गए तीन पुर्तगाली नागरिक मारियाना मोर्टागुआ, अभिनेत्री सोफिया अपारिसियो और कार्यकर्ता मिगुएल डुआर्टे हैं।

जर्जिया में सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज, प्रदर्शनकारियों की राष्ट्रपति भवन में घुसने की कोशिश नाकाम, कोबाखिद्जे सरकार कराएगी जांच

एजेंसी

त्बिलिसी (जॉर्जिया)। नये चुनाव की मांग को लेकर व्यापक स्तर पर सत्ता विरोधी प्रदर्शनों का सामना कर रहे जॉर्जिया में हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने राजधानी त्बिलिसी में शनिवार को एटोनेली स्ट्रीट स्थित राष्ट्रपति भवन का सुरक्षा घेरा तोड़ परिसर में दाखिल होने की कोशिश की। जिसके बाद स्थितियां काफी बिगड़ गईं।सुरक्षाकर्मियों ने आंसू गैस और पेपर स्प्रे का इस्तेमाल कर प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर किया। आंतरिक मामलों के मंत्रालय (एमआईए) ने रैली के दौरान हुई हिंसक घटनाओं की जांच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री इराकली कोबाखिद्जे ने आरोप लगाया है कि यूरोपीय संघ के झंडे के साथ दंगाइयों ने प्रेसिडेंशियल पैलेस के बाहर बैरिकेड्स में आग लगा दी।उन्होंने दावा किया कि जॉर्जिया में संवैधानिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के प्रयास किए जा रहे हैं। विपक्ष देश में नए सिरे से संसदीय चुनाव कराने और कैदियों की रिहाई की मांग कर रहा है। फ्रीडम स्क्वायर पर यह विरोध प्रदर्शन पिछले 311 दिनों से चल रहा है। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शनकारी शनिवार को जॉर्जिया और यूरोपियन यूनियन के झंडे लेकर त्बिलिसी के फ्रीडम स्क्वायर और रुस्तवेली एवेन्यू से मार्च करते हुए राष्ट्रपति भवन पहुंचे।

यहां प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन का सुरक्षा घेरा तोड़कर परिसर में दाखिल होने की कोशिश की।इस दौरान प्रदर्शनकारियों का सुरक्षाकर्मियों के साथ टकराव हुआ। सुरक्षाकर्मियों ने आंसूगैस, पेपर स्प्रे और वाटर कैनन का इस्तेमाल कर प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर किया। जॉर्जिया टुडे के मुताबिक प्रदर्शन को लेकर उप मंत्री अलेक्सांद्रे दारखवेलिद्जे ने कहा कि पुलिस अधिकारियों पर हमला, देश की संवैधानिक व्यवस्था में हिंसक परिवर्तन का आह्वान, सामूहिक हिंसा का आयोजन या हिस्सेदारी से संबंधित धाराओं के तहत जांच की जा रही है। चेतावनियों और मंत्रालय के आधिकारिक बयानों के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने कानूनी आदेशों का पालन नहीं किया। आयोजकों ने हिंसक आह्वान किए, एटोनेली स्ट्रीट स्थित राष्ट्रपति भवन के बैरियरों को क्षतिग्रस्त किया और इमारत में घुसने का प्रयास किया। 14 पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं। उल्लेखनीय है कि देश में साल 2024 में हुए संसदीय चुनाव के बाद से ही राजनीतिक गतिरोध चल रहा है। सत्तारूढ़ जॉर्जियन ड्रीम पार्टी इस चुनाव में धांधली के आरोपों का सामना कर रही है। इस चुनाव की निगरानी करने वाले अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने भी जॉर्जियन ड्रीम पार्टी की जीत को दोषपूर्ण बताया था। इसके बाद प्रधानमंत्री इराकली कोबाखिद्जे की अगुवाई वाली सरकार ने जॉर्जिया के यूरोपीय संघ में शामिल होने की बातचीत को स्थगित कर दिया।

दरअसल, जॉर्जिया कभी यूरोपीय संघ में शामिल होने का दावेदार रहा है लेकिन मौजूदा जॉर्जियन ड्रीम पार्टी की सरकार ने जार्जिया के यूरोपीय संघ में शामिल होने की बातचीत तब बंद कर दी जब पिछले साल हुए संसदीय चुनाव नतीजों को यूरोपीय संघ द्वारा भी संदिग्ध बताया गया और सरकार विरोधी आंदोलन को समर्थन दिया गया।

भारत-यूरोपीय संघ के बीच 14वें दौर की एफटीए वार्ता 6 अक्टूबर से

एजेंसी

नई दिल्ली। भारत-यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को लेकर 14वें दौर की वार्ता 6 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष वॉन डेर लेयेन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस साल के अंत तक एफटीए को अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा है। यूरोपीय संघ के राजदूत हर्वे डेल्फिन ने शनिवार को भारत में यूरोपीय व्यापार महासंघ (एफईबीआई) की दूसरी वार्षिक आम बैठक में यह बात कही। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष इस वर्ष के अंत तक इस समझौते को अंतिम रूप देने के लक्ष्य के साथ तेजी से बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। एफईबीआई की दूसरी वार्षिक आम बैठक में बोलते हुए हर्वे डेल्फिन ने इस बात पर जोर दिया कि भारत में पहले से ही बड़ी संख्या में यूरोपीय व्यापार मौजूद हैं, जो मुक्त व्यापार समझौता के और भी ज्यादा अवसर खोल सकता है। एफईबीआई के एक नए सर्वेक्षण के अनुसार 6,000 से ज्यादा यूरोपीय कंपनियां भारत में काम कर रही हैं और 30 लाख से ज्यादा रोजगार पैदा कर रही हैं। ये कंपनियां न केवल निवेश करती हैं, बल्कि भारत से विनिर्माण, नवाचार और निर्यात भी करती हैं, जिससे प्रधानमंत्री मोदी के 'मेक इन इंडिया' विजन में सीधा योगदान मिलता है।

गोयल ने सिंगापुर के निवेशकों से भारत में अवसर तलाशने का आग्रह किया

नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर के निवेशकों से आग्रह किया कि वे आर्थिक विकास के क्षेत्र में भारत द्वारा प्रस्तुत अवसरों पर गौर करें। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने शनिवार को सिंगापुर में भारत सिंगापुर विकास के लिए साझेदारी विषय पर निवेशकों के साथ एक बैठक को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा, मैं आप सभी से भारत द्वारा प्रदान किए जा रहे अवसरों के पैमाने पर गौर करने का आग्रह करता हूं। गोयल ने अपने संबोधन में भारत के बाजार आकार, कुशल कार्यबल और पूंजी, अनुसंधान एवं विकास तथा स्थिरता में संभावनाओं पर प्रकाश डाला। मंत्री ने तीव्र आर्थिक वृद्धि पर जोर देते हुए भारत की तीन खास विशेषताओं पर प्रकाश डाला, जिसमें बाजार का आकार, अवसर और इसके कार्यबल का कौशल। वाणिज्य मंत्री ने कहा, हम साथ मिलकर काम करने तथा भारत सिंगापुर बिजनेस राउंडटेबल द्वारा शुरू की गई विभिन्न पहलों को तेजी से आगे बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के अधिकारी अथक प्रयास कर रहे हैं तथा ऐसे मॉडल तैयार कर रहे हैं, जिनसे दोनों देशों के संबंधों को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। गोयल ने कहा कि मुझे लगता है कि एक साथ मिलकर कई नई सीमाएं हैं, जिन्हें पार करना होगा। चाहे वह पूंजी का क्षेत्र हो, अनुसंधान और विकास हो, मानव संसाधन, कौशल, प्रतिभा या शिक्षा का क्षेत्र हो, भारत और सिंगापुर मिलकर सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

6-जी प्रौद्योगिकी के विकास पर केंद्रित होगा इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025: आईएमसी सीईओ

नई दिल्ली। आगामी इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 कार्यक्रम 6-जी पारिस्थितिकी तंत्र के विकास से जुड़े सभी महत?वपूर्ण मुद्दों को जोड़ने और नई साझेदारियां बनाने पर केंद्रित होगा। डिजिटल प्रौद्योगिकी मंच इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पी. रामकृष्ण ने यह जानकारी दी। सीईओ पी. रामकृष्ण ने कहा कि एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में वैश्विक स्तर पर देश की मान्यता 6-जी प्रौद्योगिकी के विकास को आगे बढ़ाने में बेहद अहम है। उन्होंने बताया कि सरकार समर्थित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में 8-11 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। रामकृष्ण ने कहा, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 6-जी इकोसिस्टम के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभर रहा है। वैश्विक स्तर पर भारत अपनी विश्वसनीयता का प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि इंडिया मोबाइल कांग्रेस में ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, यूरोप और भारत जैसे देशों के वरिष्ठ उद्योग जगत के नेता और विशेषज्ञ शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 कार्यक्रम में 150 देशों के 7,000 से ज्यादा वैश्विक प्रतिनिधियों, 800 वक्ताओं और 400 प्रदर्शकों के भाग लेने की उम्मीद है, जहां 5-जी से 6-जी, एआई, आईओटी, हरित तकनीक और उपग्रह संचार जैसी विभिन्न तकनीकों पर विचार-विमर्श और साझेदारी पर चर्चा होगी।

अगले सप्ताह पांच नए आईपीओ की लॉन्चिंग, 24 शेयरों की होगी लिस्टिंग

नई दिल्ली। लगातार दो सप्ताह तक प्राइमरी मार्केट में बड़ी संख्या में नए आईपीओ की लॉन्चिंग होने के बाद सोमवार 6 अक्टूबर से शुरू हो रहे नए कारोबारी सप्ताह के दौरान प्राइमरी मार्केट की हलचल तुलनात्मक रूप से कम रहने वाली है। इस सप्ताह पांच नए आईपीओ लांच होने वाले हैं। इनमें से चार आईपीओ मेनबोर्ड सेगमेंट के हैं, जबकि एक आईपीओ एसएमई सेगमेंट का है। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन के लिए पहले से ओपन हुए तीन आईपीओ में भी सोमवार तक और एक आईपीओ में मंगलवार बोली लगाई जा सकेगी। इस सप्ताह होने वाली लिस्टिंग की बात करें तो 24 कंपनियां लिस्टिंग के जरिए स्टॉक मार्केट में अपने कारोबार की शुरुआत करेंगी। इनमें से पांच कंपनियां मेनबोर्ड सेगमेंट की हैं, जबकि 19 कंपनियां एसएमई सेगमेंट की हैं। इस सप्ताह के पहले दिन ही 6 अक्टूबर को नए आईपीओ के रूप में टाटा कैपिटल का 15,511.87 करोड़ रुपये का पब्लिक इश्यू सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। इसमें 8 अक्टूबर तक बोली लगाई जा सकेगी।

बैंकों के पास बिना दावे के पड़ी 1.84 लाख करोड़ की संपत्तियां असली मालिकों तक पहुंचे : वित्त मंत्री

एजेंसी

अहमदाबाद। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यहां कहा कि बैंकों और नियामकों के पास 1.84 लाख करोड़ रुपये की वित्तीय संपत्तियां बिना दावे के पड़ी हैं। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये संपत्तियां उनके असली मालिकों तक पहुंचें। केंद्रीय वित्त मंत्री ने गांधीनगर में वित्तीय क्षेत्र में लावारिस संपत्तियों पर राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान 'आपकी पूंजी आपका अधिकार' के शुभारंभ के अवसर पर अपने संबोधन में यह बात कही। सीतारमण ने राज्य के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई और बैंकों एवं वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में गांधीनगर से तीन महीने के आपकी पूंजी, आपका अधिकार अभियान की शुरुआत की। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि बैंकों और नियामकों के पास बैंक जमा, बीमा, भविष्य निधि या

शेयरों के रूप में 1.84 लाख करोड़ रुपये की वित्तीय संपत्तियाँ बिना दावे के पड़ी हैं। सीतारमण ने कहा, मैं यहां सभी से इस अभियान का राजदूत बनने के लिए कहना चाहती हूं। कृपया अपने संपर्कों से संपर्क करें और पूछें कि क्या उनके पास कोई लावारिस वित्तीय संपत्ति है। उन्होंने अधिकारियों से 3 महीने तक चलने वाले इस अभियान के दौरान इन लावारिस संपत्तियों को उनके असली मालिकों तक पहुंचाने के लिए तीन 'ए'- जागरूकता, पहुंच और कार्रवाई- पर काम करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर पंजीकरण करने और अपनी संपत्ति का दावा करने के लिए उन्हें मार्गदर्शन करने में मदद करें। वित्तीय सेवा विभाग के अनुसार 1,84,000 करोड़ रुपये वहां पड़े हैं।

ये सुरक्षित हैं। वित्त मंत्री ने कहा, मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूं कि यह पूरी तरह सुरक्षित है। आप जब चाहें, उचित कागजात के साथ आएं। आपको पैसा दिया जाएगा। सरकार इसकी संरक्षक है। यह बैंक के जनिए या सेबी के माध्यम से हो सकता है। यह किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से हो सकता है, लेकिन यह सुरक्षित अभिरक्षा में पड़ा है।

एसबीआई ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए 1.55 करोड़

एजेंसी

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष में 1.55 करोड़ रुपये का चेक प्रदान किया गया। इस अवसर पर हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पवार भी उपस्थित रहे । यह राशि एसबीआई के कर्मचारियों द्वारा राज्य में चल रहे बाढ़ राहत कार्यों में सहयोग हेतु एक दिन के वेतन को एकत्र कर प्रदान की गई। एसबीआई के मुख्य महाप्रबंधक कृष्ण शर्मा, महाप्रबंधक (हरियाणा) नीरज भारती और उप महाप्रबंधक काजल भौमिक द्वारा मुख्यमंत्री को राशि का चेक प्रदान किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देश के सबसे बड़े बैंक, एसबीआई, द्वारा हरियाणा प्रदेश के नागरिकों के प्रति उदार योगदान और निरंतर सहयोग की सराहना की।

शीर्ष 10 की सात कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 74,574 करोड़ रुपये बढ़ा

एजेंसी

मुंबई। घरेलू शेयर बाजारों में पिछले सप्ताह रही तेजी के बीच बीएसई की शीर्ष 10 में से सात कंपनियों का संयुक्त बाजार पूंजीकरण 74,574 करोड़ रुपये बढ़ा जबकि अन्य तीन में 32,233 करोड़ रुपये की गिरावट दर्ज की गयी। एचडीएफसी बैंक का बाजार पूंजीकरण (एमकैप) सबसे अधिक 30,106 करोड़ रुपये बढ़ा। एलआईसी के एमकैप में 20,588 करोड़ रुपये और भारतीय स्टेट बैंक में 9,277 करोड़ रुपये की बढ़त रही।

हिंदुस्तान यूनीलिवर का बाजार पूंजीकरण 7,859 करोड़ रुपये और आईसीआईसीआई बैंक का 3,108 करोड़ रुपये बढ़ा। बजाज फाइनेंस के एमकैप में 2,893 करोड़ रुपये और टीसीएस के एमकैप में 742 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गयी। नुकसान उठाने वालों में रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार पूंजीकरण 19,351 करोड़ रुपये, भारती एयरटेल का 12,031

करोड़ रुपये और इंफोसिस का 850 करोड़ रुपये घट गया। बाजार पूंजीकरण के मामले में 18,45,085 करोड़ रुपये के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले स्थान पर रहा। इसके बाद क्रमशः एचडीएफसी बैंक का बाजार पूंजीकरण 14,81,890 करोड़ रुपये और भारती एयरटेल का 10,80,891 करोड़ रुपये रहा।

चावल-चीनी नरम, गेहूं मजबूत, खाद्य तेलों-दालों में घट-बढ़

एजेंसी

नई दिल्ली। घरेलू थोक जिंस बाजारों में बीते सप्ताह चावल के औसत भाव में नरमी रही जबकि गेहूं में तेजी देखी गयी। चीनी के भाव भी घट गये। वहीं, खाद्य तेलों और दालों में उतार-चढ़ाव रहा। घरेलू थोक जिंस बाजारों में सप्ताह के दौरान चावल की औसत कीमत 26 रुपये घटकर सप्ताहांत पर 3,811.35 रुपये प्रति क्विंटल पर रही। वहीं, गेहूं 26 रुपये महंगा होकर 2,865.60 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका। आटे की कीमत कमोबेश स्थिर रही और सप्ताहांत पर यह 3,318.28 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा।

बीते सप्ताह सरसों तेल की औसत कीमत 65 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ी। पाम ऑयल में भी 41 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी रही। वहीं, मूंगफली तेल 145 रुपये और सोया तेल 37 रुपये प्रति क्विंटल फिसल गया। सूरजमखी तेल 20 रुपये और वनस्पति 80 रुपये प्रति क्विंटल सस्ता हुआ। दाल-दलहनों में मसूर दाल की

औसत कीमत में नौ रुपये प्रति क्विंटल की साप्ताहिक तेजी दर्ज की गयी। चना दाल की कीमत 30 रुपये और मूंग दाल की 31 रुपये प्रति क्विंटल घट गयी। तुअर दाल 107 रुपये और उड़द दाल 39 रुपये प्रति क्विंटल सस्ती हुई।

गुड़-चीनीः सप्ताह के दौरान मीठे के बाजार में गुड़ के औसत भाव 20 रुपये प्रति क्विंटल घट गये। चीनी में भी 15 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट रही।

सरकार ने 1,500 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण प्रोत्साहन योजना के लिए दिशा-निर्देश किए जारी

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 1500 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण प्रोत्साहन योजना के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दिशा-निर्देश जारी होने के साथ महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया अब 2 अक्टूबर 2025 से 1 अप्रैल 2026 तक खुली है।

खान मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में बताया कि मंत्रालय ने 3 सितंबर, 2025 को कैबिनेट की मंजूरी के बाद 1,500 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण प्रोत्साहन योजना के लिए आधिकारिक तौर पर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। विस्तृत दिशा-निर्देश जारी होने के बाद ये योजना अब 02 अक?टूबर से छह महीने की अवधि के लिए 01 अप्रैल, 2026 तक आवेदन के लिए खुली है। मंत्रालय ने कहा कि योजना के दिशा-निर्देश और आवेदन करने का लिंक खान मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस योजना

का उद्देश्य द्वितीयक स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों को निकालने के लिए भारत की पुनर्चक्रण क्षमता को बढ़ावा देना है और यह राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत एक प्रमुख पहल है। योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन विंडो अब कार्यशील है। प्रोत्साहन योजना राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का एक प्रमुख घटक है। इसका उद्देश्य देश में द्वितीयक स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों के पृथक्करण और उत्पादन के लिए पुनर्चक्रण क्षमता विकसित करना है।

पात्र फीडस्टॉक स्रोत ई-कचरा, प्रयुक्त लिथियम-आयन बैटरी और अन्य स्क्रैप सामग्री हैं। अपेक्षित लाभार्थी बड़े और स्थापित पुनर्चक्रणकर्ता और छोटे और नए पुनर्चक्रणकर्ता (स्टार्ट-अप सहित) दोनों होंगे। यह योजना नई इकाइयों में निवेश के साथ-साथ क्षमता विस्तार/आधुनिकीकरण और मौजूदा इकाइयों के विविधीकरण पर लागू होगी। योजना प्रोत्साहन पुनर्चक्रण मूल्य श्रृंखला के लिए होगा, जो महत्वपूर्ण खनिजों के वास्तविक निष्कर्षण में है, न कि केवल 'ब्लैक मास' उत्पादन में शामिल मूल्य श्रृंखला के लिए।

अक्टूबर में दो दिन में एफपीआई ने बेची 3,842 करोड़ की इक्विटी

एजेंसी

मुंबई। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने अक्टूबर में महज दो दिन में 3,842 करोड़ रुपये की इक्विटी की शुद्ध बिकवाली की। इस महीने 02 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवकाश के कारण शेयर तथा दूसरे पूंजी बाजारों में अब तक दो दिन ही कारोबार हुआ है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस दौरान एफपीआई ने इक्विटी में 3,842 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली की। इक्विटी समेत पूंजी बाजार से उनकी कुल शुद्ध निकासी 1,262 करोड़ रुपये रही।

इस दौरान, म्यूचुल फंड में उन्होंने 281 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली की, जबकि डेट में 2,681 करोड़ रुपये की शुद्ध खरीद की। हाइब्रिड इनस्ट्रूमेंट में भी उन्होंने 181 करोड़ रुपये की शुद्ध लिवाली की।मई के बाद से एफपीआई पूंजी बाजार में लगातार बिकवाल रहे हैं। सितंबर में उन्होंने 12,571 करोड़ रुपये, अगस्त में 20,635 करोड़ रुपये, जुलाई में 5,261 करोड़ रुपये और जून में 7,769 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली की थी। इस साल अब तक एफपीआई भारतीय पूंजी बाजार से 85,872 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली कर चुके हैं।

मॉयल ने सितंबर में अब तक का सर्वश्रेष्ठ 1.52 लाख टन उत्पादन किया

एजेंसी

नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की मैंगनीज अयस्क उत्पादक कंपनी मॉयल लिमिटेड ने अबतक का सर्वश्रेष्ठ उत्पादन किया है। मॉयल का उत्पादन सितंबर में 3.8 फीसदी बढ़कर 1.52 लाख टन पर पहुंच गया। इस्पात मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि मॉयल ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही सितंबर 2025 में 1.52 लाख टन उत्पादन हासिल किया, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 3.8 फीसदी की वृद्धि है। यह कंपनी का सितंबर का सबसे अच्छा प्रदर्शन और सर्वश्रेष्ठ उत्पादन है। मत्रालय के मुताबिक 30 सितंबर को समाप्त चालू वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में मॉयल ने 4.42 लाख टन का अपना अबतक का सर्वोच्च दूसरी तिमाही उत्पादन दर्ज किया है, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही की तुलना में 10.3

फीसदी की ठोस वृद्धि है। कंपनी ने 3.53 लाख टन की बिक्री भी दर्ज की, जो साल-दर-साल 18.6 फीसदी अधिक है, जो मजबूत बाजार मांग और कुशल आपूर्ति श्रृंखला निष्पादन का संकेत है। इस्पात मंत्रालय के मुताबिक अन्वेषणात्मक कोर ड्रिलिंग 5,314 मीटर तक पहुंच गई, जो सितंबर 2024 की तुलना में 46 फीसदी की उल्लेखनीय बढ़ोतरी है, जो कंपनी के अन्वेषण और दीर्घकालिक संसाधन विकास पर बढ़ते जोर को दर्शाता है। मॉयल ने अपने अन्वेषण प्रयासों को और मजबूत करते हुए दूसरी तिमाही के दौरान 21,035 मीटर अन्वेषणात्मक कोर ड्रिलिंग की, जिससे यह दूसरी तिमाही का अब तक का सर्वश्रेष्ठ ड्रिलिंग प्रदर्शन रहा तथा पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 4.1 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। मॉयल लिमिटेड के इस प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अजीत कुमार सक्सेना ने कहा, प्रमुख मानकों में वृद्धि, मॉयल की अपनी परिचालन उत्कृष्टता को सुदृढ़ करने और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अपनी सभी संचालित खदानों में अन्वेषण पर निरंतर जोर देने के साथ मॉयल मैंगनीज क्षेत्र में अग्रणी बने रहने के लिए अपने भंडार/संसाधनों को बढ़ाने की अच्छी स्थिति में है।

पहली बार 100 अरब डॉलर के करीब पहुंचा देश का स्वर्ण भंडार

एजेंसी

मुंबई। मौजूदा भू-राजनैतिक परिस्थितियों के मद्देनजर दुनिया के दूसरे केंद्रीय बैंकों की तरह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) भी स्वर्ण भंडार लगातार बढ़ा रहा है और अब यह पहली बार 100 अरब डॉलर पर पहुंचने के करीब है। केंद्रीय बैंक के आंकड़ों के अनुसार, 26 सितंबर को समाप्त सप्ताह में स्वर्ण भंडार 2.238 अरब डॉलर बढ़कर 95.017 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो इसका अब तक का उच्चतम स्तर है।

विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार दूसरे सप्ताह गिरावट देखी गयी, लेकिन स्वर्ण भंडार लगातार पांचवें सप्ताह बढ़ा है। यह दिखाता है कि केंद्रीय बैंक अब विदेशी मुद्रा से ज्यादा सोने पर भरोसा कर रहा है और लगातार स्वर्ण भंडार बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। इसमें कुछ योगदान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में जारी तेजी का भी है। उल्लेखनीय है कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार 26

सितंबर को समाप्त सप्ताह में 2.334 अरब डॉलर घटकर 700.236 अरब डॉलर रह गया। इसमें विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति 4.393 अरब डॉलर घटकर 581.757 अरब डॉलर पर आ गयी। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत अब रूस से पिछड़कर दुनिया में पांचवें स्थान पर आ गया है। चीन, जापान और स्विटजरलैंड क्रमशः पहले तीन स्थान पर हैं। हालांकि स्वर्ण भंडार को छोड़ दिया जाये, तो भारत अब भी चौथे स्थान पर कायम है।

गैर-बासमती चावल विकास कोष की प्रबंधन समिति के सदस्य बने प्रेम गर्ग

एजेंसी

नई दिल्ली। भारतीय चावल निर्यातक महासंघ (आईआरईएफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेम गर्ग को गैर-बासमती चावल विकास कोष (एबीडीएफ) की प्रबंध समिति के सदस्य नियुक्त किये गये हैं। इस कोष का गठन केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) के अधीन किया गया है। प्राधिकरण ने अपने सदस्यों को इसकी जानकारी देते हुये इसे समस्त चावल कारोबारियों के लिए गर्व का क्षण बताया। उसने कहा कि इससे यह सुनिश्चित होगा कि भारतीय चावल निर्यातकों की आवाज सीधे गैर-बासमती चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समर्पित नीति-निर्माण मंच पर पहुंचेगी। समिति गैर-बासमती चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एनबीडीएफ फंड के इस्तेमाल और वैश्विक बाजारों में भारतीय चावल प्रतिस्पर्धी बने रहें इसके लिए नीति-निर्माण की निगरानी करेगी। इसके अलावा वह सरकार, एपीईडीए और उद्योग से हितधारकों के साथ संयोजन भी सुनिश्चित करेगी। आईआरईएफ ने विश्वास जताया कि डॉ. गर्ग के समिति में शामिल होने से उसके सदस्यों और वृहत स्तर पर सभी चावल निर्यातकों के हितों की रक्षा होगी।

शेयर बाजार पर दिखेगा वैश्विक कारकों का असर

एजेंसी

मुंबई। घरेलू शेयर बाजारों में पिछले सप्ताह रही तेजी के बाद आने वाले सप्ताह में बाजार पर वैश्विक कारकों का असर दिखेगा। निवेशकों की नजर भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता पर होगी। इसके अलावा रिजर्व बैंक द्वारा पिछले सप्ताह किये गये बैंकिंग सुधारों का असर भी बाजार पर जारी रह सकता है। अगले सप्ताह से कंपनियों के दूसरी तिमाही के वित्तीय परिणाम भी आने शुरू होंगे जिनमें दिग्गज सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी टीसीएस का परिणाम गुरुवार को आयेगा। एचएसबीसी की सेवा क्षेत्र की पीएमआई रिपोर्ट सोमवार को जारी होनी है।

बीते सप्ताह में बाजार में चार दिन ही कारोबार हुआ। पहले दो दिन बाजार में गिरावट रही जबकि रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति बयान के बाद अगले दो दिन तेजी देखी गयी। गुरुवार को गांधी जयंती के मौके पर शेयर बाजार बंद रहे। बीएसई के 30 शेयरों वाले संवेदी सूचकांक सेंसेक्स में 780.71 अंक (0.97 प्रतिशत) की

साप्ताहिक तेजी रही और सप्ताहांत पर यह 81,207.17 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 0.97 प्रतिशत यानी 239.55 अंक चढ़कर शुक्रवार को 24,894.25 अंक पर पहुंच गया।

सप्ताह के दौरान सार्वजनिक बैंकों के सेक्टर में तेजी रही। धातु समूह में भी जबरदस्त तेजी देखी गयी। निजी बैंकों, तेल एवं गैस, वित्त, ऑटो, फार्मा और रियलिटी सेक्टरों में भी जबरदस्त तेजी रही। मझौली और छोटी कंपनियों में ज्यादा तेजी रही। सप्ताह के दौरान निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 1.87 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 1.81 प्रतिशत चढ़ा।

सेंसेक्स की कंपनियों में टाटा मोटर्स का शेयर सबसे अधिक 6.39 प्रतिशत की साप्ताहिक बढ़त में रहा। कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर 5.34 प्रतिशत, बीईएल का 4.22, टाइटन का 3.76 और टाटा स्टील का 3.43 प्रतिशत चढ़ा। सनफार्मा के शेयर में 2.99 फीसदी, ट्रेंट में 2.85, पावर ग्रिड में 2.66. एक्सिस बैंक में 2.42, इटरनल में 2.30 और एचडीएफसी बैंक में 2.07 प्रतिशत की तेजी रही। अडानी पोर्ट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनीलिवर, एनटीपीसी और भारतीय स्टेट बैंक के शेयर भी एक प्रतिशत से दो प्रतिशत के बीच चढ़े।मारुति सुजुकी में सबसे अधिक 2.84 प्रतिशत की साप्ताहिक गिरावट रही। भारती एयरटेल का शेयर 1.10 फीसदी, रिलायंस इंडस्ट्रीज का 1.04 फीसदी और टेक महिंद्रा का 0.48 फीसदी टूट गया।

'पट्टा बांधने का टाइम आ गया है...' वीकेंड के वार में सलमान लेंगे अमाल-अभिषेक और

अशनूर कौर

की क्लास, सामने आया प्रोमो

बिग बॉस 19 में हर दिन नया नया ड्रामा देखने को मिल रहा है. जैसे-जैसे गेम आगे बढ़ रही है , वैसे-वैसे कंटेस्टेंट्स के बीच कहासुनी भी बढ़ती जा रही है. लेटेस्ट एपिसोड में खूब ड्रामा देखने को मिला जहां अभिषेक बजाज और अमाल मलिक में हाई-वोल्टेज लड़ाई हुई. अमाल ने अभिषेक को खुली धमकियां दीं जिसके बाद घर का माहौल बिगड़ गया. अब वीकेंड के वार के प्रोमो में सलमान को सभी की क्लास लगाते देखा जा सकता है.प्रोमो में साफतौर पर देखा जा सकता है कि सलमान काफी गुस्से में हैं. सलमान ने अशनूर, अभिषेक और अमाल की जमकर क्लास लगाई और सभी को उनके बर्ताव के लिए खूब डांटा. सलमान ने अशनूर को उनके एरोगेंट बिहेवियर के लिए काफी सुनाया. इस बार वीकेंड के वार में सलमान सभी की क्लास लगाते नजर आने वाले हैं.

'अभिषेक-अमाल का झगड़ा'

प्रोमो में ये भी देखा जा सकता है कि अमाल, सलमान के सामने अभिषेक से ऊंची आवाज में बात करते हैं, जिसके बाद सलमान को गुस्सा होते देखा जा सकता है. दरअसल, बीते एपिसोड में अभिषेक बजाज और अमाल मलिक के बीच भयंकर झगड़ा हुआ था. बात सिर्फ गाली-गलौज तक नहीं रुकी, बल्कि हाथापाई की नौबत आ गई और अमाल ने परिवार खत्म करने जैसी बड़ी धमकी भी दे डाली. हद तब पार हो गई जब नाराज घरवालों ने अपने माइक उतारकर बिग बॉस को ही चेतावनी दे डाली.

दूसरे दिन के कैप्टेंसी टास्क के दौरान पहले केयरटेकर बने जीशान कादरी ने तान्या मित्तल को बुलाया. तान्या ने तुरंत नेहल को कैप्टेंसी की दौड़ से बाहर कर दिया. अगली केयरटेकर बनीं नेहल चुडासमा, जिन्होंने फरहाना को बुलाया, और फरहाना ने बिना देर किए तान्या को रेस से बाहर कर दिया. नेहल के बाद अशनूर कौर के केयरटेकर बनने की बारी आई, और यहीं से घर में महा-बवाल शुरू हो गया. जैसे-जैसे अशनूर अपनी बात बोलती गई, अमाल और अभिषेक के बीच जबरदस्त कहासुनी शुरू हो गई.

हमारा दुख कोई नहीं सुनना चाहता... बॉलीवुड एक्ट्रेस जान्हवी कपूर ने क्यों कह दी ऐसी बात?

बॉलीवुड एक्ट्रेस जान्हवी कपूर अपने समय की मशहूर एक्ट्रेस श्रीदेवी की बेटी हैं. मां की तरह वे भी फिल्मों में हाथ आजमा रही हैं और उन्हें अच्छी शुरुआत भी मिल गई है. एक्ट्रेस को स्टारकिड होने की वजह से कई दफा ट्रोल्स का शिकार भी बनना पड़ जाता है. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के प्रमोशन के दौरान कई सारे मुद्दों पर बातें की. उन्होंने बताया कि कैसे स्टार किड होने की वजह से उनके स्ट्रगल्स को कोई समझता नहीं है और उन्हें अलग दृष्टि से देखा जाता है. एक्ट्रेस ने मायूसी जताई और कहा कि उनका दुख कोई सुनना नहीं चाहता क्योंकि लोगों को लगता है कि एक्ट्रेस प्रिवलेज्ड हैं.

इंटरव्यू में बातचीत के दौरान जान्हवी कपूर से उनके करियर के अब तक के स्ट्रगल्स के बारे में पूछा गया. इसका जवाब देते हुए एक्ट्रेस ने कहा- कोई इंटरेस्टेड नहीं है सुनने के लिए. क्योंकि हम प्रिवलेज्ड बैकग्राउंड से हैं तो कोई सुनना थोड़े ना चाहता है. लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है. लेकिन मुझे ये भी लगता है कि हमें इतनी कम्प्लेन भी नहीं करनी चाहिए. क्योंकि हमें जो भी मिला है उसके हम बहुत आभारी हैं. अगर हम यहां बैठकर बोलेंगे कि नहीं हमारे लिए बहुत मुश्किल है, जबकी मुश्किल तो सबके लिए होता है.

इनसाइडर-आउटसाइडर की जंग पसंद नहीं

जान्हवी कपूर ने आगे कहा- मुझे पर्सनली ये आउटसाइडर-इनसाइडर के बीच का डिविजन अच्छा नहीं लगता है. हालांकि आउटसाइडर्स का जो स्ट्रगल होती है वो बहुत अलग होता है. उसे हम नहीं समझ सकते हैं. ऐसे में हमारा ये कम्प्लेन करना कि हम बहुत चीजों से गुजरे हैं ज्यादा फर्क नहीं पैदा करता है. और कोई सुनना भी नहीं चाहता है.

कैसी है सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की कमाई ?

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी फिल्म की बात करें तो इस फिल्म में जान्हवी कपूर के अपोजिट वरुण धवन नजर आए हैं. इसके अलावा फिल्म में सान्या मल्होत्रा और रोहित शराफ जैसे कलाकार भी हैं. फिल्म में अक्षय ओबेरॉय और मनीष पॉल ने भी एक्टिंग की है. इसका निर्देशन शशांक खैतान ने किया है. फिल्म को जनता से मिश्रित रिस्पॉन्स मिल रहा है. हालांकि इसकी कमाई पहले दिन तो ठीक रही थी.ओपनिंग डे पर फिल्म ने 9.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. वहीं दूसरे दिन इस फिल्म की कमाई में गिरावट देखने को मिली है. इसका कलेक्शन दूसरे दिन 5.50 करोड़ का रहा है. इस लिहाज से देखा जाए तो फिल्म ने दो दिन में 14.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है. देखने वाली बात होगी कि पहले वीकेंड में फिल्म कितना कमाती है.

जब अमिताभ बच्चन को घंटों तक इंतजार करवाती थीं रेखा, गुस्से में बिग बी ने उठा लिया था ऐसा कदम!

'सदी के महानायक' अमिताभ बच्चन और दिग्गज एक्ट्रेस रेखा ने बॉलीवुड में कभी अपने रिश्ते से जमकर सुर्खियां बटोरी थीं. बिग बी शादीशुदा और दो बच्चों के पिता होने के बावजूद रेखा के प्यार में पड़ गए थे. जबकि वो एक्ट्रेस से उम्र में 12 साल बड़े भी हैं. लेकिन, एक्ट्रेस को भी इन चीजों से कोई ऐतराज नहीं था. हालांकि बिग बी के शादीशुदा होने के चलते इस रिश्ते को कोई मंजिल नहीं मिल पाई.80 के दशक की शुरुआत तक अमिताभ बच्चन और रेखा का रिश्ता खत्म हो गया था. आज भी अमिताभ और रेखा के रिश्ते को लेकर फिल्मी गलियारों में काफी बातचीत होती है. इसी कड़ी में आज हम आपको रेखा और बिग बी से जुड़ा एक खास किस्सा बताने जा रहे हैं, जब महानायक रेखा से नाराज हो गए थे और उन्होंने एक्ट्रेस की शिकायत डायरेक्टर से कर दी थी.

रेखा पर क्यों भड़के थे अमिताभ ?

एक न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक अमिताभ बच्चन और रेखा अपने शुरुआती दिनों में एक दूसरे के प्रति प्रोफेशनल चीजों के चलते कड़वाहट रखते थे. दोनों की एक फिल्म की शूटिंग एक बार कोलकाता में हो रही थी. शूटिंग का वक्त सुबह 9 बजे तय किया गया था. बिग बी तो सेट पर 7 बजे ही पहुंच जाते थे और वो 9 बजे तक शॉट्स के लिए तैयार भी हो जाते थे. दूसरी ओर रेखा समय पर नहीं पहुंचती थीं. वो कोलकाता में शॉपिंग करने लगती थीं और कई घंटे तक सेट पर नहीं आती थीं. इस वजह से रेखा पर बिग बी को गुस्सा आ गया था. क्योंकि अमिताभ तैयार होकर शूट के लिए एक्ट्रेस का इंतजार करते रहते थे.

डायरेक्टर से की थी रेखा की शिकायत

बताया जाता है कि रेखा की लेटलतीफी का सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा. जब पानी बिग बी के सिर से ऊपर जा चला गाया. जिसके बाद अमिताभ बच्चन अपनी पिक्चर के डायरेक्टर के पास गए और उन्होंने एक्ट्रेस की शिकायत उनसे कर दी. हालांकि बिग बी को डायरेक्टर से जिस जवाब की उम्मीद थी, उन्हें वो नहीं मिला. डायरेक्टर ने अभिनेता से कहा था कि ये अब रेखा की आदत बन चुकी है.

क्या विजय देवरकोंडा और

रश्मिका मंदाना

ने चोरी छिपे कर ली सगाई? साथ में तस्वीर हुई वायरल

दक्षिण भारतीय सिनेमा के चर्चित जोड़ी विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने मीडिया की निगाह से दूर रहकर एक निजी समारोह में सगाई कर ली है. कपल ने अभी सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा नहीं की है, लेकिन उनके फैंस के बीच यह खबर तेजी से फैल रही है. बताया जा रहा है कि दोनों की शादी फरवरी 2026 में होने वाली है.

सगाई समारोह बेहद छोटी और चुनी हुई सभा में संपन्न हुआ. इसमें केवल परिवार के सदस्य और करीबी मित्र ही शामिल थे. इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि विजय और रश्मिका अपनी निजी जिंदगी को सार्वजनिक हलचल से दूर रखना चाहते हैं. रू९ हद्ग2ह्य की रिपोर्ट के अनुसार, उनका शांत और गोपनीय रवैया इस समय प्राइवेसी को बनाए रखने की उनकी प्राथमिकता को दर्शाता है.

रश्मिका के साड़ी लुक से बढ़ी शगुन की अटकलें

कुछ दिन पहले रश्मिका ने साड़ी में अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थीं, जो देखते ही देखते वायरल हो गए. फैंस ने इन लुक्स को सगाई के अवसर से जोड़कर चर्चा तेज कर दी. इस वायरल पोस्ट ने कपल की प्रेम कहानी और सगाई की खबरों को और हवा दी है.

अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं

विजय और रश्मिका दोनों ने अब तक मीडिया के सामने इस सगाई की पुष्टि नहीं की है. रू९ हद्ग2ह्य की रिपोर्ट के मुताबिक, इस समय दोनों अपनी प्राइवेसी को प्राथमिकता दे रहे हैं और सार्वजनिक घोषणा करने से पहले सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं.

फैंस में खुशी, सोशल मीडिया पर बधाइयों की बौछार

सगाई की खबर से उनके प्रशंसकों में खुशी की लहर दौड़ गई है. सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर विजय और रश्मिका की तस्वीरें और वीडियो शेयर किए जा रहे हैं. लोग जोड़ी को बधाई दे रहे हैं और उनकी शादी के दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं.

फरवरी 2026 में होगी भव्य शादी

सगाई के बाद अब सभी की नज़रें फरवरी 2026 पर टिकी हैं, जिस दिन यह जोड़ी बंधन में बंधेगी. दोनों शादी की तैयारियों में जुट चुके हैं — और यह दक्षिण भारतीय सिनेमा की एक यादगार और चर्चित शादी बनने की पूरी संभावना है.

मिशन शक्ति के अंतर्गत बालिकाओं को मिली आत्मनिर्भरता की नई दिशा

लखनऊ

उत्तर प्रदेश सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत आज पूरे प्रदेश में अंर्तराष्ट्रीय बालिका सप्ताह थीम पर "ड्राइविंग माय ड्रीम्स' कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस अभिनव पहल का उद्देश्य बालिकाओं और महिलाओं को कौशल विकास के साथ-साथ आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की ओर अग्रसर करना है। इस कार्यक्रम की विशेषता यह रही कि प्रत्येक जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों से 100-100 बालिकाओं और महिलाओं का चयन कर उनके लिये 'निशुल्क ड्राइविंग का प्रशिक्षण प्रदान करने की मुहीम शुरू की गई। प्रत्येक जनपद में यह प्रशिक्षण न्यूनतम 1 माह हेतु आयोजित किया जायेगा। चयनित प्रतिभागियों को प्रशिक्षकों

द्वारा ड्राइविंग से जुडे बुनियादी नियम, सडक सुरक्षा, ट्रैफिक संकेत, आपातकालीन परिस्थितियों में वाहन नियंत्रण और महिला सुरक्षा उपायों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है।

"ड्राइविंग माय ड्रीम्स' केवल वाहन चलाने तक सीमित कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह बालिकाओं को उनके सपनों की उडान देने का एक सशक्त माध्यम है। इससे वे न केवल रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर तलाश सकेंगी, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होकर समाज की मुख्यधारा से भी जुडेंगी।

सरकार का लक्ष्य है कि प्रशिक्षण उपरांत इन बालिकाओं को औपचारिक ड्राइविंग लाइसेंस दिलवाया जाए, जिससे वे व्यावसायिक स्तर पर भी आगे बढ़ सके अथवा अपने दैनिक कार्यों हेतु किसी और पर निर्भर न रहें।

प्रदेश के विभिन्न जनपदों से प्रेरक झलकियाँ भी सामने आई। कहीं ग्रामीण पृष्ठभूमि की बेटियों ने पहली बार हैंडल / स्टीयरिंग संभालकर आत्मविश्वास की नई अनुभूति की, तो कहीं महाविद्यालयों की छात्राओं ने इसे अपनी शिक्षा और करियर में नया आयाम जोडने वाला कदम बताया। कार्यक्रम में शामिल प्रशिक्षको ने बताया कि बालिकाओं में सीखने की ललक और उत्साह देखकर यह स्पष्ट होता है कि वे इस पहल से अपने जीवन में बडा परिवर्तन लाएँगी।

महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश की अपर मुख्य सचिव सचिव लीना जोहरी ने कहा, "ड्राइविंग माय ड्रीम्स' केवल ड्राइविंग का प्रशिक्षण देने वाला कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह बेटियों और महिलाओं के सपनों को दिशा देने का अभियान है। मिशन शक्ति की भावना है कि हर बेटी आत्मनिर्भर बने और जीवन के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाए।"

'ड्राइविंग माय ड्रीम्स बालिकाओं की इसी नई उडान का प्रतीक है, जो न केवल उनकी व्यक्तिगत प्रगति बल्कि पूरे प्रदेश की सामाजिक और आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगा।

उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा उक्त कार्यक्रमों के माध्यम से मिशन शक्ति के 5वें चरण में दिनाक 22 सितम्बर 02 अक्टूबर, 2025 के मध्य कुल 13,12,997 व्यक्तियों को जागरूक किया गया है जिसमें महिलायें पुरुष, बालक और बालिकायें सभी शामिल हैं।

संभल में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद ध्वस्तीकरण को लेकर कागजात पेश करने का निर्देश

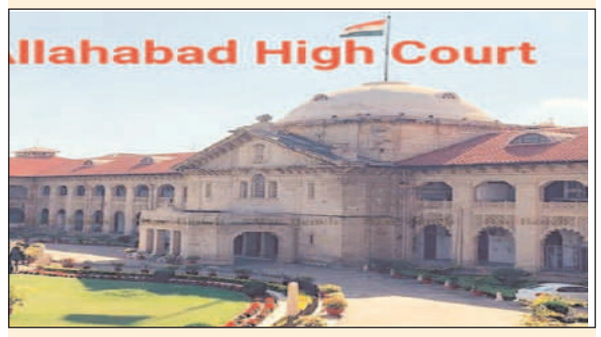

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संभल में तालाब और सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद के ध्वस्तीकरण के मामले में संबंधित कागजात पेश करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने मसाजिद शरीफ गोसुलबारा रावां बुजुर्ग और मस्जिद के मुतवल्ली मिंजर की ओर से दाखिल याचिका पर उनके अधिवक्ताओं को सुनकर दिया है। दशहरा अवकाश के दौरान यह याचिका दाखिल कर छुट्टी के दिन अर्जेंट बेसिस पर सुनवाई की मांग की गई। याचिका में मस्जिद, बारात घर और अस्पताल के ध्वस्तीकरण के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है।

कहा गया है कि बारात घर को ध्वस्त कर दिया गया है। ध्वस्तीकरण के लिए दो अक्टूबर गांधी जयंती व दशहरे की छुट्टी का दिन चुना गया, जबकि बुलडोजर कार्रवाई के दौरान भीड़ की वजह से कोई बड़ा हादसा या बवाल भी हो सकता था। इस कार्रवाई के पीछे आरोप है कि बारात घर तालाब की जमीन पर बना हुआ है जबकि मस्जिद का कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर बना हुआ है।

दोपहर एक बजे से करीब सवा घंटे हुई सुनवाई में मस्जिद पक्ष को कोई अंतरिम राहत नहीं मिली। लेकिन कोर्ट ने मस्जिद पक्ष को आवश्यक कागजात पेश करने का निर्देश देते हुए शनिवार सुबह 10 बजे मामले में पुनः सुनवाई करने को कहा है। याचिका में राज्य सरकार, डीएम व एसपी संभल, एडीएम, तहसीलदार और ग्राम सभा गोसुलबारा रावां बुजुर्ग को पक्षकार बनाया गया है।

किशोरी से छेड़खानी और मारपीट के मामले में दोषी को उम्र कैद की सजा

उरई। उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन में किशोरी से छेड़खानी और मारपीट के मामले में पोक्सो कोर्ट ने को दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार रुपये का जुमार्ना लगाया है।

अपर शासकीय अधिवक्ता रणकेंद्र सिंह भदौरिया और विश्वजीत सिंह गुर्जर ने संयुक्त रूप से बताया कि यह घटना 31 जुलाई 2020 की है। चौरसी नई बस्ती निवासी रोहित वर्मा ने एक गांव की किशोरी के घर में घुसकर उसके साथ छेड़खानी की थी। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट भी की। पीड़ित के पिता ने तत्काल पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामला पंजीकृत किया।

पुलिस ने 23 अगस्त 2020 को इस मामले में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया था। 16 फरवरी 2021 को आरोपी रोहित के खिलाफ आरोप तय किए गए। लगभग पांच साल तक चले इस ट्रायल के दौरान, अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के सामने छह गवाह पेश किए।

को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने आरोपित रोहित वर्मा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जुमार्ने की 50 हजार रुपये की राशि में से, कोर्ट ने 30 हजार रुपये की राशि पीड़िता को देने का भी आदेश दिया है।

बीते दिनों हुई चोरी का पुलिस नही कर पाई खुलासा, पीड़ित ने सीओ से की शिकायत

उरई। कोंच कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला आजाद नगर में 25 और 26 सितम्बर की मध्यरात्रि को चोरों ने एक घर में धावा बोलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस अभी तक चोरी का खुलासा नहीं कर सकी है। इस मामले में पीड़ित ने को सीओ कोंच परमेश्वर प्रसाद से मिलकर पुलिस की लापरवाही की शिकायत कर चोरों के गिरफ्तारी की मांग की है।

पीड़ित गृहस्वामी नूरुउद्दीन ने बताया कि 25 और 26 सितम्बर की मध्य रात्रि उनके घर में दो चोर घुसे। 31 हजार रुपये कैश लेकर भागने के दौरान मेरे पुत्र ने एक चोर को पकड़ लिया और उससे चार हजार रुपये छीन लिए थे। छीना झपटी में चोरों ने सिर में लाठी मार कर बेटे को घायल कर फरार हो गए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन आज तक चोरों की गिरफ्तारी की नहीं कर सकी। फिलहाल पीड़ित गृहस्वामी ने चोरों की गिरफ्तारी और कार्यवाही की मांग की है।

इस मामले में सीओ परमेश्वर प्रसाद का कहना है कि टीमें लगातार लगी हुई है। पीड़ित ने शिकायती पत्र दिया गया है और हम इस चोरी की घटना का जल्द से जल्द अनावरण करेंगे।

जौनपुर : चार करोड़ की एमडीएमए तस्करी के आरोप में चार गिरफ्तार

जौनपुर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की बदलापुर कोतवाली पुलिस और बाराबंकी की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एमडीएमए तस्करी के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से एक किलोग्राम 30 ग्राम एमडीएमए, पांच एंड्रॉयड मोबाइल फोन और दो मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं।

अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) देहात आतिश कुमार सिंह ने को पत्रकारों को बताया कि टीम ने गुरुवार देर रात को मिरशादपुर ओवरब्रिज सर्विस लेन पर चेकिंग के दौरान दो मोटरसाइकिलों पर सवार चार युवकों को गिरफ्तार किया।

बेटियां हैं आज की सशक्त नीति निर्माता : डॉ भारत

सुलतानपुर। उत्तर प्रदेश के जिला सुलतानपुर में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मिशन शक्ति के पांचवें चरण के तहत एक अभिनव पहल की गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. भारत भूषण ने मिशन शक्ति की इस एकीकृत पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह अभियान महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलम्बन से संबंधित है और इससे बेटियों में नेतृत्व क्षमता का विकास होगा।

नगर के पीएम श्री केशकुमारी बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने को सांकेतिक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी और उपमुख्य चिकित्सा अधिकारी की भूमिका निभाई। श्रेया ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अदिति तिवारी ने अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी और आयुषी पाण्डेय ने उपमुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रतीकात्मक पदभार संभाला।

पदभार संभालने के बाद, सांकेतिक अधिकारियों ने सबसे पहले उपस्थिति पंजिका का अवलोकन किया। उन्होंने देर से आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को समय पर कार्यालय पहुंचने के निर्देश दिए। इसके उपरांत, उन्होंने सभी उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत महिलाओं से संबंधित विभिन्न योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की विस्तृत समीक्षा की गई। इन अभियानों का उद्देश्य महिलाओं को व्यापक स्वास्थ्य जांच, पोषण और जागरूकता प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त, जनपद में चल रहे दुर्गा पूजा महोत्सव की तैयारियों की जानकारी ली गई और सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों तथा प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को आकस्मिक सेवाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य शिविर आयोजित होने वाले चिन्हित स्थलों पर सभी अधिकारी-कर्मचारियों को समय पर उपस्थित रहने को कहा गया।

आपराधिक केस लम्बित होने पर निरस्त नहीं कर सकते शस्त्र लाइसेंस : उच्च न्यायालय

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि आपराधिक केस लम्बित होने के आधार पर शस्त्र लाइसेंस निरस्त नहीं किया जा सकता। धारा 17(3) आयुध अधिनियम के तहत केवल लोक शांति व लोक सुरक्षा को शस्त्र से खतरा होने पर ही लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। कोर्ट ने याची के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के जिलाधिकारी जौनपुर व आयुक्त वाराणसी के आदेशों को रद्द कर दिया है और जिलाधिकारी जौनपुर को दो माह में नियमानुसार आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने अनुराग जायसवाल की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची का कहना था कि उसके खिलाफ शस्त्र के दुरुपयोग का आरोप नहीं है। और न ही उसके किसी आचरण से लोक शांति व सुरक्षा को खतरे की आशंका है। वह अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्र रखना चाहता है। ऐसे में जिलाधिकारी उसके शस्त्र लाइसेंस को निरस्त नहीं कर सकते। केवल आपराधिक केस लम्बित रहना शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने का आधार नहीं हो सकता। लाइसेंस निरस्त करने की शर्तें धारा 17 मे लिखी है। कोर्ट ने कहा दो लोगों में दुश्मनी है, इससे नहीं कहा जा सकता कि लोक शांति व सुरक्षा को खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुरेश सिंह यादव केस में साफ कहा है कि आपराधिक केस लम्बित होना शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने का आधार नहीं हो सकता।

ड्रोन उड़ान की करें प्रभावी मॉनिटरिंग, अफवाहों को रोके

प्रयागराज। ड्रोनों के उड़ान की प्रभावी मॉनिटरिंग की जाय और ग्रामीण क्षेत्रों अफवाहों को रोके जाने एवं चोरी के प्रकरणों में एफआइआर दर्ज कराते हुए घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए। यह बात को प्रयागराज सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कड़ा निर्देश दिया।

उन्होंने पुलिस आयुक्त ड्रोनों के उड़ान की प्रभावी मानिटरिंग कराते हुए अफवाहों को रोके जाने एवं चोरी के प्रकरणों में एफआइआर दर्ज कराते हुए घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने के लिए कहा है।समय सीमा में निपटाएं जमीन विवाद

बैठक में समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री ने सभी तहसीलों एवं थानों में कार्यपद्धति में गुणात्मक सुधार लाये जाने एवं सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित किए जाने के लिए कहा है। जमीन से जुड़े विवादों, धारा-24 एवं दाखिल खारिज से सम्बंधित प्रकरणों को निर्धारित समय सीमा में अनिवार्य रूप से निस्तारित करें।रवि की बुआई करने को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों उर्वरक मंत्री ने कहा कि आलू एवं रबी फसल की बुआई का समय नजदीक होने के दृष्टिगत किसानों को डीएपी खाद व अन्य उर्वरकों की उपलब्धता में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जिलाधिकारी को विधानसभावार जनप्रतिनिधियों, एवं अधिकारियों एवं सहकारी समितियों के साथ बैठक करते हुए खाद की उपलब्धता बनाये रखने के निर्देश दिए है। मंत्री ने राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए धारा-24 एवं दाखिल खारिज से सम्बंधित प्रकरणों को समयसीमा में निस्तारित किए जाने के लिए कहा है।

उन्होंने कहा कि जमीन से सम्बंधित छोटे से छोटे मामलों को प्राथमिकता से संज्ञान में लेते हुए सम्बंधित पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी मौके पर जाकर उसका निस्तारण बिना पक्षपात के पारदर्शिता के साथ समय से सुनिश्चित करें, जिससे कि उसके कारण लोगो के बीच अनावश्यक विवाद न उत्पन्न होने पाये। उन्होंने कहा कि लेखपाल का पद राजस्व विभाग का एक महत्वपूर्ण अंग है। उन्होंने कहा कि कभी-कभी लेखपालों की कार्यप्रणाली के बारे में शिकायतें प्राप्त होती रहती है। उन्होंने ऐसे लेखपालों को जिनकी शिकायत अधिक है तथा जो लम्बे समय से एक ही क्षेत्र में तैनात है, उनको चिन्हित करते हुए उनके कार्यक्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए कहा है।

मंत्री ने विद्युत विभाग की समीक्षा करते हुए विद्युत व्यवस्था को सुचारू बनाये जाने एवं विद्युत बिल में अनियमित्ता से सम्बंधित शिकायतों को निस्तारित करने और खराब होने वाले ट्रांसफार्मरों को समयसीमा में बदलवाने के निर्देश दिए है।

50 हजार का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल

अमेठी। उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी में देर रात 50,000 रुपये का इनामी शातिर अंतर्जनपदीय बदमाश मनीष यादव उर्फ गणेश यादव उर्फ मिंटू पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल हो गया। उसके बाएं पैर में गोली लगी है। बदमाश मुख्य रूप से गौ तस्करी की वारदातों में शामिल रहता था। रात करीब दो बजे मुखबिर की सूचना पर स्वाट व सर्विलांस टीम और थाना रामगंज पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बैर घाट के पास बदमाश से आमना-सामना हो गया।

जिले के अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने शनिवार को बताया कि मौके से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस 315 बोर का तथा गौ तस्करी में प्रयुक्त की जाने वाली एक मोटरसाइकिल बरामद की है। घायल बदमाश मनीष यादव पुत्र शिवलाल मूल रूप से कैथा थाना अलीनगर जनपद चंदौली का निवासी है। उसके खिलाफ कई गंभीर मुकदमे पूर्व में ही दर्ज हैं और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

मस्जिद की दीवार पर बम फेंकने के मामले में रिजवान की गिरफ्तारी पर रोक

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रयागराज के खुल्दाबाद थाना क्षेत्र की एक मस्जिद की दीवार पर बम फेंकने के मामले में आरोपी रिजवान की गिरफ्तारी पर पुलिस रिपोर्ट दाखिल होने तक रोक लगा दी है। दो अभियुक्तों जीशान व अनीस को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय तथा न्यायमूर्ति जफीर अहमद की खंडपीठ ने याची अधिवक्ता इरफान अहमद मलिक को सुनकर दिया है। इनका कहना है कि याची निर्दोष है। सह अभियुक्तों के बयान पर उसे फंसाया गया है। एफआईआर व केस डायरी देखने से साफ है कि उसके खिलाफ बी एन एस की धारा 109(1) के अपराध का खुलासा नहीं किया गया है। कोई व्यक्ति बम से घायल नहीं हुआ है। धारा 288 का अपराध बन सकता है, किन्तु इसमें छह माह की कैद या पांच हजार जुमार्ना या दोनों की सजा मिल सकती है। इसलिए याची को गिरफ्तार न किया जाए। कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट पेश होने या याचिका तय होने जो जल्दी हो तक खुल्दाबाद थाने में दर्ज एफआईआर के अंतर्गत याची को गिरफ्तार न करने का निर्देश दिया है।

नौकरी का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने वाला आरोपित गिरफ्तार

बलिया। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में जरूरतमंदों को पैसे और नौकरी का लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कराने और देवी-देवताओं की मूर्तियां तोड़ने के लिए उकसाने के आरोप में को एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने शाम पत्रकारवार्ता में बताया कि भीमपुरा थाना क्षेत्र के बाराडीह लवाईपट्टी गांव के विनोद कुमार के खिलाफ कई संगीन आरोप है। इन्हीं आरोपों में एक यह भी आरोप है कि वह बाराडीह लवाईपट्टी गांव की हरिजन बस्ती में कुछ बाहरी लोगों के साथ गांव के स्थानीय लोगों को एकत्र करके ईसाई धर्म का प्रचार- प्रसार कर रहा है।

बेटियां पूरे कुल-समाज और राष्ट्र को आलौकिक करती है: अस्मिता लाल

बागपत से मेरी बेटी, मेरे कुलदीपक का आगाज

बागपत। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में "मेरी बेटी, मेरी कुलदीपक" अभियान की शुरूआत हुई है। इसका उद्देश्य बेटियों के महत्व को समाज में नए दृष्टिकोण से स्थापित करना है। इस अभियान के तहत, 35 जागरूक परिवारों को सम्मानित किया गया। जो गर्व के साथ बेटियों का पालन-पोषण कर रहे हैं। इन परिवारों को जिलाधिकारी अस्मिता लाल ने को कुलदीपक और पौधा देकर सम्मानित किया है।

समाज में बेटियों को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने को लेकर जिलाधिकारी ने एक अभियान की शुरूआत की है। इसको लेकर को कलेक्ट्रेट सभागार में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने मेरी बेटी, मेरी कुलदीपक अभियान का शुभारम्भ करते हुए कहा कि बेटियां केवल परिवार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि वह रोशनी हैं जो पूरे

कुल, समाज और राष्ट्र को आलौकित करती है।

अभियान का उद्देश्य बेटियों को सशक्त बनाना और उनकी शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान को बढ़ावा देना है।

उन परिवारों को विशेष पहचान और सम्मान देना होगा जो बेटियों का गर्व से पालन-पोषण कर रहे हैं। शिक्षा और सुरक्षा से जुड़े सरकारी कार्यक्रमों को जमीनी स्तर पर लागू करना पड़ेगा। नई पीढ़ी में यह संदेश पहुंचाना होगा कि बेटियां ही असली परिवर्तन की वाहक हैं।

जिलाधिकारी ने कहा कि बेटियां परिवार और समाज की रोशनी हैं और उन्हें अवसर, शिक्षा और सम्मान मिलने पर वे जीवन के हर क्षेत्र में समाज का गौरव बढ़ाती हैं। इस अभियान से समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने और उन्हें सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। इस दौरान 35 परिवारों को सम्मानित किया।

Published, printed and owned by Rajesh.Chauhan, printed at Dinesh Sharma 19, DSIDC Sheds, Scheme 3, Okhla Phase-2 New Delhi -110020 and published at BG 6 305 B Paschim Vihar New Delhi --110063 Editor Rajesh.Chauhan. E mail ID-rajeshchauhan4569@gmail.com, Contact No. - 9873104569, RNI No.- DLHIN/25/A2321